आज का विचार

जीवन केकुछ संबंध ऐसे होते हैं जो किसी पद-प्रतिष्ठा के मोहताज नहीं होते, वे स्नेह और विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

पंचकूला । रविवार, 12 अप्रैल, 2026 वर्ष 1, अंक 239, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: HRHIN/25/A2164 Established 2025 www.citydarpan.com

कांग्रेस के नेता मंडी में जाने की बजाय कांग्रेस शासित प्रदेशों का हाल देखकर आएं: नायब सैनी

विकसित दादरी रैली में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने साधे निशाने

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता से किये संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में दो रोज पहले भी श्रमिकों से किए गए मजदूरी बढ़ाने के संकल्प को सरकार ने पूरा करते हुए उनका मासिक वेतन 19 हजार 425 रुपये तक सुनिश्चित किया है। लेकिन,कांग्रेसी सिर्फ बरगलाने में जुटे है, कभी किसानों को झूठ बोल कर गुमराह करते हैं तो कभी दूसरे वर्ग को। कांग्रेस के नेता मंडी में जाने की बजाय हिमाचल जाएं, कर्नाटक जाएं, तेलंगाना जाएं और पता करके आएं कि क्या वहां की जनता से किये वायदे उनकी सरकारों ने पूरे किए हैं या नहीं। मुख्यमंत्री शनिवार को चरखी दादरी में विकसित दादरी रैली में बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 540 करोड़ 98 लाख रुपये की 43 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दादरी विधानसभा क्षेत्र को दी। कार्यक्रम के दौरान रैली के आयोजक एवं विधायक श्री सुनील सतपाल सांगवान ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी भी मौजूद थी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि चरखी-दादरी की मिट्टी अपने आप में गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। यहां की हवा में शौर्य है, यहां के कण-कण में वीरता बसती है। सन-1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, आजादी की लड़ाई हो अथवा आजादी के बाद चीन व पाकिस्तान से होने वाले युद्ध हों, यहां के जवानों ने सदा वीरता की नई मिसाल कायम की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र का समान विकास करने की दिशा में काम कर रही है। पिछले 11 वर्षों में दादरी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 271 घोषणाएं की गई हैं। इनमें से 201 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 58 पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने अब तक दादरी विधानसभा क्षेत्र में 1 हजार 364 करोड़ 60 लाख रुपये की लागत के विकास कार्य करवाए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 303 करोड़ 30 लाख रुपये के काम हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जनकल्याण के काम गति से कर रही है। आज समय की मांग है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करें। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता का विश्ववास जीतना है। विपक्ष केवल आरोप लगाता है, लेकिन हमारे पास काम का रिपोर्ट कार्ड है। हमने जो कहा, वह कर-के दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दादरी का विकास अब तिगुणी रफ़्तार से होगा। चरखी-दादरी को दिसम्बर, 2016 में नया जिला बनाया गया, वहीं गांव झोझू कलां और बोंद को ब्लॉक बनाया गया। सरकार इस क्षेत्र में भी तेज गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दादरी के लिए हाल ही में पेश किए गए बजट में खास परियोजनाएं बनाई गई है। इसके तहत चरखी दादरी सहित 10 जिलों में प्राकृतिक व जैविक किसानों को कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5 जिलों के 44 जलघरों के टैंकों को आरसीसी लाइनिंग में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें चरखी दादरी के अलावा हिसार, रोहतक, झज्जर व भिवानी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह चरखी दादरी, हांसी, झज्जर व मांडी खेड़ा के जिला अस्पतालों में अतिरिक्त 100 बिस्तरीय भवनों का निर्माण भी किया जाएगा।दादरी के विधायक एवं रैली के आयोजक श्री सुनील सतपाल सांगवान ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इस सरकार ने युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां दी है। इसी प्रकार से विकास के कार्यों में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के जो नेता पारदर्शिता की पॉलिसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसी पार्टी के नेताओं की संतान को राजपत्रित पदों पर नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के समक्ष नौकरी की केवल एक ही शर्त रखी है, और वह है उनकी योग्यता व बौद्धिक क्षमता। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को दादरी हलका के विकास के लिए विभिन्न मांगों का घोषणा-पत्र भी सौंपा।

इस दौरान सांसद चौधरी श्री धर्मबीर सिंह, विधायक श्री उमेद पातुवास, श्री पवन खरखौदा, श्री अनिल यादव, श्री विनोद भ्याणा, श्री कपूर सिंह वाल्मिकी, श्री मुकेश शर्मा, श्री कंवर सिंह यादव, पूर्व मंत्री श्री जेपी दलाल, जिलाध्यक्ष चरखीदादरी श्री सुनील इंजीनियर, जिला परिषद चेयरमैन श्री मनदीप डालावास, जिला प्रभारी श्री महेश चौहान, नगर परिषद दादरी चेयरमैन श्री बक्शीराम सैनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

भाजपा की सरकार बनी, तो 'सिंडिकेट राज' खत्म करेंगे, घुसपैठियों को खदेड़ेंगे : शाह

बंगाल चुनाव-2026: केंद्रीय गृहमंत्री ने बाकुंडा रैली में राज्यसरकार को घेरा

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के ओंडा-विष्णुपुर क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए दावा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा।

सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर सिंडिकेट का प्रभाव है। चाहे वह निर्माण कार्य हो या रोजमर्रा की जरूरतें। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने जनता से 23 अप्रैल को कमल के निशान पर वोट देने की अपील करते हुए कहा प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताइए, हम बंगाल से सिंडिकेट राज को समाप्त कर देंगे। अमित शाह ने बांकुड़ा क्षेत्र के विकास को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा।उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में इस इलाके की उपेक्षा हुई है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ा। साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार बनने पर विष्णुपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और क्षेत्रीय विकास को गति दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी अमित शाह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा।उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है और स्थिति चिंताजनक है।

भाजपा सरकार बनने पर 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने पर ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा और मतदाता सूची से भी अवैध नाम हटाए जाएंगे। अपने संबोधन में शाह ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा भी दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित होगा। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की।सभा के दौरान अमित शाह ने राज्य सरकार पर कई घोटालों-जैसे शिक्षक भर्ती, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य मामलों में संलिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर इन सभी मामलों की जांच के लिए आयोग गठित किया जाएगा और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।

पश्चिम बंगाल के कटवा रैली में उमड़ी भीड़ का मोदी ने जारी किया वीडियो, दिया विपक्ष को संदेश

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के दौरान कटवा रैली को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनसभा में आई भीड़ को रेखांकित करते हुए राज्य का मिजाज बताया। उन्होंने कहा कि आप भीड़ को देखकर इस राज्य का मिजाज समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूरबा बर्धमान जिले के कटवा में जनसभा के दौरान सभा में उमड़ी भीड़ का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने सभा से पहले का दृश्य दिखाया। वीडियो रिकॉर्ड करते समय उन्होंने कहा कि भाजपा की रैलियों में उमड़ी भीड़ 4 मई के नतीजों की झलक है और पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे आप बंगाल का मिजाज देख सकते हैं। अभी सुबह के 11-11:30 बजे हैं और यह मेरी आज की पहली जनसभा है। हेलीपैड पर ही हजारों लोग मौजूद हैं। यह अद्भुत है।

थारू समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी सरकार: योगी आदित्यनाथ

एजेंसी (हि.स.)
लखीमपुर खीरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखीमपुर खीरी के लोगों को बड़ी सौगात दी। महात्मा ज्योतिबा फुले व महाराणा सांगा के जन्मदिवस के एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जनपद में माफिया पालने वाली पेशेवर अपराधियों की सरकार महाराणा प्रताप व महाराणा सांगा के वंशजों पर अत्याचार और झूठे मुकदमे दर्ज करती थी। संघर्ष करने वाले थारू समाज के जिन लोगों पर सपा सरकार ने मुकदमे दर्ज किए थे, हमारी सरकार उन सारे मुकदमों को वापस लेगी। अब आप पर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार साथ खड़ी है और आपके संघर्ष को सम्मान दे रही है। इसके साथ ही सीएम ने फिर चेताया कि माफिया बनने का प्रयास करने वाले मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर लें। सरकार किसी माफिया को पनपने, गरीबों का हक छीनने और नौजवानों की नौकरी पर डकैती नहीं डालने देगी।

मुख्यमंत्री ने चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित कार्यक्रम में नदियों द्वारा भूमि क्षरण से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2350 परिवारों व थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भौमिक अधिकार पट्टों का आवंटन किया और पलिया, श्रीनगर, निघासन व गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्रों की 817 करोड़ रुपये की 314 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। सीएम ने थारू जनजाति के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति देखी और अपनी संस्कृति को बचाकर रखने के लिए उनकी सराहना भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उप्र के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को यहां बसाया गया था। आपकी तीन-तीन पीढ़ियां चली गईं, लेकिन कभी हक नहीं मिल पाया। दशकों की अधूरी यात्रा आज पुनर्वास कार्यक्रम के साथ बढ़ रही है। उन्होंने कहा चंदन चौकी इस जनपद का गौरव है। यहां वनवासी संस्कृति की जड़ें, स्वाभिमान और तराई की उर्वरता साथ फलती-फूलती है। चंदन चौकी व आसपास दर्जनों थारू बाहुल्य गांव हैं, जो पहचान के लिए मोहताज थे। कभी वन, पुलिस व राजस्व विभाग द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था।

आजादी में योगदान देने वाले भी अधिकार से रहे वंचित

सीएम योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए लोगों ने देश की आजादी के लिए सब कुछ खोया। ब्रिटिशरों ने इन्हें यातनाएं (काला पानी, देशनिकाला, फांसी) दीं। आजादी के बाद तत्कालीन सरकार ने उन्हें बसाया तो, लेकिन जमीन का हक उपलब्ध नहीं कराया। देश की आजादी में योगदान देने वाले लोग आजाद भारत में अपने अधिकार से वंचित थे। 1976 में थारू समाज को इन गांवों में जमीन देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें जमीन का स्वामित्व नहीं मिला। 1955 में पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया। चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित कार्यक्रम में योगी ने विभिन्न लाभार्थियों को भी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र, आवास की चाबी व चेक सौंपे। सीएम योगी के हाथों भौमिक अधिकार पत्र प्राप्त करने वालों में बालकृष्ण, रामखेलावन, भज्जीराम, रामनरेश व रामकुमार शामिल रहे। आंगनवाड़ी भर्ती के तहत ऊषा देवी (ध्यानपुर), संध्या कुमारी (पुरैना) तथा मीना कुमारी (सूरमा) को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ध्यानपुर की बल्लू देवी, शीतल व बेबी को अपने आवास की चाबी मिली।

भारत किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम : राजनाथ

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तीन दिवसीय दौरे पर शनिवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल व महानगर भाजपा अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद रक्षामंत्री गोमती नगर (लखनऊ) जनकल्याण महासमिति के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए।

कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी चुनौती से निपटने में भारत सक्षम है। भाजपा सरकार के रहते कोई भी संकट देश में आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त भंडार है इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बाद उत्पन्न हालात से कोई देश अछूता नहीं है लेकिन भारत ने उन चुनौतियों पर विजय पाने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है।

राजनाथ ने कहा कि मुझे यह देखकर भी बड़ी खुशी होती है कि हमारा लखनऊ रक्षा क्षेत्र में भी बढ़-चढ़ कर योगदान दे रहा है। यह लखनऊ के लिए गर्व की बात है कि इसे आगरा और कानपुर के साथ डिफेंस नोड घोषित किया गया। अब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण भी शुरू हो चुका है। गर्व की बात यह है कि इसकी पहली खेप हमारी सेना को सौंप भी दी गई है। इसके साथ ही रक्षा उपकरणों से जुड़े कई और छोटे-बड़े कारखाने भी यहां स्थापित हो रहे हैं। लखनऊ का विकास, बेहद सुनियोजित योजना के तहत चल रहा है। यह विकास की गंगा है जिसकी धारा में, गरीब का, व्यापारी का, बुजुर्ग का और नौजवान का, सबका कल्याण समाया है। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि लखनऊ वासियों का रहन-सहन सुख-सुविधाओं से सम्पन्न और परिपूर्ण रहे।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और अन्य योजनाएं ज्योतिबा फुले के विचारों के अनुरूप : नितिन नवीन

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक समानता के उनके विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उन्होंने फुले के समाज सुधार के कार्यों को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और अन्य योजनाएं उनके आदर्शों-विचारों के अनुरूप हैं।

शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने मीडिया में जारी एक बयान में कहा कि ज्योतिबा फुले के योगदान को देश आज भी याद करता है।

उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले ने पहले बालिका विद्यालय की स्थापना से लेकर सती प्रथा खत्म करने जैसे कई ऐतिहासिक कार्य किए, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ह्यबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओह्न अभियान से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने की पहल का उल्लेख किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, जो ज्योतिबा फुले के आदर्शों के अनुरूप है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को समाज में समान भागीदारी और सम्मान दिलाना है।

देश में चल रहा है किसानों के विकास का महायज्ञ : केंद्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

एजेंसी (हि.स.)
भोपाल

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के लिए कृषि का विकास आवश्यक है। हमारे लिए किसान ही भगवान है और उनकी सेवा ही हमारी पूजा है। देश में किसानों के विकास का महायज्ञ चल रहा है। हमारा लक्ष्य 140 करोड़ देशवासी को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। हमें कृषि उत्पादन बढ़ाना है और कृषि की लागत भी घटानी है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान शनिवार को मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय स्थित दशहरा मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आयोजित ₹उन्नत कृषि महोत्सव-2026₹ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व में देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं। वे स्वयं एक किसान हैं। आज रायसेन की पवित्र धरा पर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और कृषि का संगम हो रहा है। यह किसानों के लिए एक पाठशाला की तरह है, जहां किसानों को कृषि की नवीन तकनीकें सीखने का अवसर मिलेगा।केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि रायसेन जिला कृषि सहित हर क्षेत्र में आगे हैं, यहां की धान और गेहूं दुनियाभर में प्रसिद्ध है। रायसेन में दो विश्व धरोहर सांची और भीमबैठिका हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमें शक्तिशाली विकसित भारत बनाना है। देश को मजबूत इरादों वाले प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री मिले हैं।

उन्होंने कहा कि इस आयोजन में कृषि से किसानों को आय बढ़ाने के लिए एकीकृत खेती पर जानकारी प्रदान की जाएगी। इंटीग्रेडेट फॉर्मिंग से एक एकड़ में दो लाख तक की आय प्राप्त की जा सकती है। खेती से जुड़े अलग-अलग विषयों पर 20 सत्र आयोजित किए गए हैं। इसमें बीज से लेकर बाजार तक किसानों को हर तरह के सपोर्ट की जानकारी दी जाएगी। मिट्टी की जांच के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसान अपनी रुचि के अनुसार सत्रों में बैठकर जानकारियां लें। इस क्षेत्र के किसानों की तकदीर बदलने के लिए ही यह महोत्सव मनाया जा रहा है।

केन्द्रीय मंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पूरा वर्ष ही कृषि कल्याण को समर्पित कर दिया है। उन्होंने बताया कि उन्नत कृषि महोत्सव में 12 अप्रैल को उनके संसदीय क्षेत्र के 4-5 जिलों का कृषि रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय इसे रायसेन, भोपाल, विदिशा, सीहोर से शुरू कर पूरे देश में लागू करेगा। उन्होंने कहा कि रायसेन को हार्टिकल्चर हब बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दलहन मिशन के अंतर्गत किसानों को तुअर, मसूर, उड़द, मूंगफली के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की अलग छवि बन रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश में कृषि क्षेत्र की सफलता की पहचान बन चुके हैं। किसानों की मेहनत से अब हमारा देश दोगुना खाद्यान्न निर्यात कर रहा है। मध्य प्रदेश का केवल रायसेन जिला ही दुनिया के 47 से अधिक देशों को बासमती चावल का निर्यात कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में बीईएमएल के पहले रेल कारखाने का भूमि-पूजन हुआ है और आज वे किसानों को अपना मार्गदर्शन देने आए हैं। भारत का हर क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के लिए शुभंकर केन्द्रीय मंत्री हैं। खेत के श्रमवीर किसानों और सीमा पर शूरवीर जवानों के सम्मान में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में उन्नत कृषि महोत्सव का यह आयोजन इन दोनों की गरिमा को बढ़ाने वाला है। जवानों से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकारों में प्रदेश के किसानों को गेहूं और धान का समुचित मूल्य मिला है।

सुक्खू ने ऊना के हरोली में 260 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास

बल्क ड्रग पार्क के साइट विकास कार्य और कामकाजी महिला छात्रावास का भी किया शिलान्यास

एजेंसी (हि.स.)

ऊना

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को हरोली उपमंडल के पोलियां बीत में निर्माणाधीन राष्ट्रीय महत्व की बल्क ड्रग पार्क परियोजना के अंतर्गत 250 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले साइट विकास एवं आधारभूत संरचना कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने पंजुआना में 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले कामकाजी महिला छात्रावास की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है।

उन्होंने अधिकारियों को इसके कार्यों की गति को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 6 से आठ महीनों के भीतर यहां धरातल

सीएम सुक्खू ने भरी विकास की हुंकार

पर इसका कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई दें। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा आने वाले समय में यह क्षेत्र एक आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होकर उभरेगा।

उन्होंने कहा कि दो हजार करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहा यह औद्योगिक परिसर देश के फार्मा क्षेत्र को नई मजबूती देगा। यह परियोजना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स के निर्माण में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी तथा दवाइयों के कच्चे माल के लिए बाहरी देशों पर निर्भरता कम करेगी। देशभर में केवल तीन बल्क ड्रग पार्क विकसित किए जा

रहे हैं, जिनमें से एक हरोली में स्थापित हो रहा है। यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वयं संचालित करने का निर्णय लिया है। केंद्र और राज्य सरकार इस योजना में 1-1 हजार करोड़ रुपये का समान निवेश कर साझेदारी के आधार पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं और हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में पांचवें स्थान तक पहुंचा है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर प्रदेश हितों की अनदेखी की गई है, लेकिन राज्य सरकार हिमाचल के अधिकारों और हितों की आवाज मजबूती से केंद्र के समक्ष उठाकर प्रदेश को विकास की नई दिशा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मनरेगा को बंद कर केंद्र सरकार ने गरीबों के हितों पर प्रहार किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत छात्रों को मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

मिड डे मील वर्करों की बैठक, 22 जून की हड़ताल सफल बनाने का आह्वान

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

शिमला जिले के सुन्नी खंड में मिड डे मील वर्कर यूनियन (सीटू से संबंधित) की एक बैठक शनिवार को पुष्पा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में मिड डे मील वर्करों ने भाग लिया और अपनी लंबे समय से लंबित समस्याओं तथा मांगों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान यूनियन नेताओं ने 22 जून को प्रस्तावित प्रदेशव्यापी हड़ताल और शिमला में होने वाली विशाल रैली को सफल बनाने का आह्वान किया।

बैठक को सीटू शिमला जिला कोषाध्यक्ष बालक राम, यूनियन नेता पुष्पा शर्मा, चंपा देवी और शीला देवी ने संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि मिड डे मील वर्करों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं और अब उन्हें मनवाने के लिए संघर्ष तेज करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, ताकि वर्करों को राहत मिल सके। बैठक में वर्करों ने मांग उठाई कि उन्हें हरियाणा सरकार की तर्ज पर सात हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाए और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के अनुसार दस महीने के बजाय बारह महीने का वेतन तुरंत लागू किया जाए। इसके अलावा वर्करों को ग्रेच्युटी, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सुविधाओं के दायरे में लाने की भी मांग की गई। यूनियन नेताओं ने यह भी कहा कि मिड डे मील वर्करों की नियुक्ति से जुड़ी 25 बच्चों की शर्त हटाई जाए और केंद्रीय रसोई, क्लस्टर योजना, ठेके पर काम देने और गैर-सरकारी संस्थाओं को काम सौंपने जैसे फैसले वापस लिए जाएं। साथ ही 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार मिड डे मील वर्करों को मजदूर का दर्जा देने की मांग भी दोहराई गई, ताकि उन्हें न्यूनतम वेतन सहित अन्य श्रम कानूनों का लाभ मिल सके। बैठक में यह मांग भी उठाई गई कि मिड डे मील योजना को 10+2 तक के बच्चों के लिए लागू किया जाए, वर्करों को नियमित छुट्टियां दी जाएं, हर महीने की पहली तारीख को समय पर वेतन मिले और साल में दो वर्दियां दी जाएं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती में मिड डे मील वर्करों को प्राथमिकता देने और अतिरिक्त काम के लिए अलग से भुगतान करने की मांग भी रखी गई। यूनियन नेताओं ने कहा कि बंद या मर्ज किए जा रहे स्कूलों के मिड डे मील वर्करों को दूसरे स्कूलों में समायोजित करने की प्रक्रिया जारी रखी जाए। चुनाव के दौरान उनसे पोलिंग पार्टियों के लिए भोजन बनवाने का काम न लिया जाए, और यदि ऐसा काम लिया जाता है तो अन्य कर्मचारियों की तरह यात्रा भत्ता और दिहाड़ी दी जाए।

साथ ही प्रत्येक स्कूल में दो मिड डे मील वर्करों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और शिक्षा विभाग के 21 अगस्त 2023 के आदेश को सख्ती से लागू करने की भी मांग की गई।

नशा तस्करी में तीन गिरफ्तार वाहन से लाखों रुपये कैश बरामद

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

शिमला ज़िले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। जिला शिमला पुलिस की कुमारसैन थाना टीम ने बीती रात नाकाबंदी के दौरान एक इनोवा गाड़ी से 9 किलो अफीम और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क से जुड़े आगे-पीछे के संबंधों की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुमारसैन थाना की टीम क्षेत्र में गश्त और नियमित नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान हरियाणा नंबर की एक इनोवा गाड़ी (एचआर-38-आर-6525) को जांच के लिए रोका गया। गाड़ी में नेपाल मूल के तीन लोग सवार थे। शक होने पर जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उनके कब्जे से 9.28 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। तलाशी के दौरान पुलिस को वाहन से 12 लाख रुपये नकद भी मिले। इतनी बड़ी

रकम मिलने के बाद पुलिस को संदेह है कि यह पैसा मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी लेन-देन का हिस्सा हो सकता है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह नकदी नशा बेचकर कमाई गई थी या किसी बड़ी डील के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय चक्रा बहादुर, 41 वर्षीय एन बहादुर और 44 वर्षीय मोहन साही के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 और 29 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन के साथ बरामद नकदी को भी कब्जे में ले लिया गया है।

तीन दिन में पंचायत चुनाव के तीन रोस्टर जारी होना चिंताजनक : राजीव बिंदल

शिमला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों से जुड़े रोस्टर में बार-बार बदलाव को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी रोस्टर को लेकर बन रही स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक है और इससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है डॉ. बिंदल ने शनिवार को एक बयान में कहा कि प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि तीन दिनों में तीन अलग-अलग रोस्टर कैसे जारी हो रहे हैं और हर रोस्टर में आरक्षण का स्वरूप अलग-अलग क्यों दिखाई दे रहा है। उनका आरोप है कि एक दिन रोस्टर जारी होता है, अगले दिन गांवों की जनसंख्या बदलने के आधार पर नया रोस्टर जारी हो जाता है और फिर तीसरे दिन फिर से बदलाव हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति से लोगों का भरोसा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के मन में यह संदेह पैदा हो गया है कि जो रोस्टर आज जारी हुआ है, वह कुछ दिनों बाद भी वही रहेगा या नहीं। उनके मुताबिक यह स्थिति पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। डॉ. बिंदल ने राज्य सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध जता रहे हैं।

विनय कुमार ने किया 17 लाख की लागत से निर्मित संपर्क मार्ग का लोकार्पण

एजेंसी (हि.स.)

नाहन

विधायक रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र विनय कुमार ने आज संगड़ाह के समीप जवगाधार से जलशक्ति विभाग के पम्प हाउस तक 17 लाख की लागत से निर्मित सम्पर्क मार्ग का लोकार्पण किया।

इस सम्पर्क मार्ग के बनने से इस क्षेत्र के लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संगड़ाह पहुँचने के लिए वैकल्पिक मार्ग की सुविधा मिलेगी। इसके उपरांत विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संगड़ाह का निरीक्षण किया जहां उन्होने मरीजों का कुशलक्षेम पुछा तथा चिकित्सालय की व्यवस्था को जांचा। विनय कुमार ने जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होने स्थानीय लोगों को नगर पंचायत संगडाह तथा संगडाह ग्राम पंचायत ग्रामीण बनने की बधाई देते हुए कहा कि यह विधानसभा क्षेत्र हिमाचल निमार्ता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की

कर्मभूमि तथा डॉक्टर प्रेम सिंह की जन्म भूमि रही है । उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन तीनों महानुभूतियों की बदौलत आज रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि में लगातार अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संगडाह नगर पंचायत बनने से इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी तथा भविष्य में ददाहु तथा नोहराधार ग्राम पंचायतो को नगर पंचायत बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह नवगठित नगर पंचायत संगडाह में आगामी चुनाव के दौरान आम सहमति बनाकर काबिल लोगों को आगे आने का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के निराकरण के लिए 155 ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे जिससे लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण होगा।

संक्षिप्त-समाचार

आधी रात मकान से टकराया डंपर, चालक की मौके पर मौत

शिमला। शिमला ज़िले के रामपुर उपमण्डल में आधी रात एक सड़क हादसा सामने आया, जब एक डंपर अनियंत्रित होकर एक मकान से जा टकराया। हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोगों की नींद खुल गई। रामपुर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान नेपाली मूल के राजत (26) पुत्र अमृत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यह मामला दिनेश कुमार पुत्र भगत राम मेहता निवासी रामपुर के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल की रात करीब 12 बजकर 20 मिनट पर अंकुश वर्कशॉप के बाहर अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। जब लोग बाहर निकले तो देखा कि एक डंपर (नंबर HP063-5542) पास ही स्थित कपूर मेहता के मकान से टकराया हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। डंपर मकान में फंसा हुआ था, जिसे जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकालकर सड़क पर लाया गया। जब वाहन की जांच की गई तो चालक सीट के पीछे झुकी हालत में चालक रजत (26) पुत्र अमृत सिंह निवासी गांव गनमा, डाकघर व तहसील देहलिक, जिला देहलिक (नेपाल) मृत पाया गया। इस हादसे में अंकुश ऑटोमोबाइल्स के पास खड़ी एक अन्य गाड़ी (नंबर HP75-5755) भी डंपर की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके की स्थिति को देखते हुए शुरूआती जांच में हादसे का कारण डंपर चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार माना जा रहा है।

अनंतनाग में पुलिस ने कई अभियानों में छह नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया

अनंतनाग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने शनिवार को कई अभियानों में छह नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए। शांगुस में पट्टी शेखपोरा निवासी गुलाम रसूल शेख के पुत्र रियाज अहमद शेख के आवास पर छापेमारी के बाद रियाज और दौदपोरा ब्राह निवासी मोहम्मद लतीफ के पुत्र आदिल लतीफ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लगभग 5.75 किलोग्राम गांजा बरामद किया और एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 33/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया। संगम चौक पर गुलाम मोहम्मद लोन के पुत्र और नटीपोरा संगम निवासी साकिब अहमद लोन को 140 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया। बिजबेहरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 84/2026 दर्ज की गई। इसी प्रकार बुमजू केपी रोड पर नाकाबंदी के दौरान न्यू कॉलोनी मट्टन निवासी अली मोहम्मद मोची के पुत्र रियाज अहमद मोची को लगभग 5.24 किलोग्राम चरस पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में मट्टन पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 37/2026 दर्ज की गई है। इसके अलावा त्तरासू में चीरपोरा निवासी गुलाम हसन के पुत्र एजाज अहमद लोन के आवास पर तलाशी अभियान के दौरान 2.225 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 36/2026 दर्ज की गई।

राजौरी की सड़कों पर बढ़ती ट्रैफिक में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किये

राजौरी। राजौरी की सड़कों पर बढ़ती ओवरलोडिंग की घटनाओं ने अब ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में वायरल हो रहे फोटो में ऑटो रिक्शा को अत्यधिक सामान लादकर सड़कों पर चलते देखा गया जो नियमों की खुली अवहेलना का उदाहरण है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि वाहन पर क्षमता से कहीं अधिक सामान लादा गया है जो किसी भी समय गिरकर बड़ा हादसा कर सकता था। इसके बावजूद वाहन का बिना किसी रोक-टोक के सड़कों पर चलना ट्रैफिक पुलिस की निगरानी पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले के कई प्रमुख मार्गों–राजौरी शहर, राजौरी-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, राजौरी-पुंछ मार्ग और अन्य व्यस्त सड़कों पर इस तरह की ओवरलोडिंग आम होती जा रही है लेकिन कार्रवाई नगण्य है। सामाजिक कार्यकताओं के अनुसार इस तरह के ओवरलोडेड वाहन न केवल चालक बल्कि आम जनता के लिए भी गंभीर खतरा हैं। अचानक ब्रेक या संतुलन बिगड़ने पर सामान गिरने से बड़े हादसे हो सकते हैं। यह घटना साफ तौर पर ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही और प्रवर्तन में कमी को उजागर करती है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे वाहन बिना किसी डर के सड़कों पर कैसे दौड़ रहे हैं। जनता ने उच्चाधिकारियों से मांग की है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी जवाबदेही तय की जाए और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पुंछ नगर में कुत्ते के काटने की स्थिति में तुरंत आवश्यक कदम उठाने की अपील की

पूँछ। पुंछ नगर में कुत्तों के काटने के मामलों में बढ़ौतरी को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. परवेज अहमद खान ने एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परामर्श जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने और कुत्ते के काटने की स्थिति में तुरंत आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। सीएमओ ने बताया कि काटे गए स्थान को तुरंत साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि संक्रमण और रेबीज वायरस के खतरे को कम किया जा सके। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि बिना किसी देरी के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उचित इलाज कराएं और समय पर एंटी-रेबीज टीकाकरण करवाएं। डॉ. खान ने घाव पर मिर्च पाउडर, तेल या किसी भी पारंपरिक घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से सख्त मना किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं और सही इलाज में देरी का कारण बनते हैं।

शिमला में भाजपा कार्यालय में मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सांसद और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए कठिन परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष किया और शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे मजबूत माध्यम बनाया। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं,

जितने उनके समय में थे। उन्होंने कहा कि उस दौर में जब समाज में असमानता अधिक थी, तब उन्होंने वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का साहसिक काम किया। उनका यह प्रयास आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को भी विशेष रूप से याद किया और कहा कि दोनों ने मिलकर महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया, जिसका असर आज भी दिखाई देता है। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों पर चलते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार काम कर रही हैं। इस मौके पर नेताओं और कार्यकताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को समाज तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता तथा समानता के उनके संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया।

दृष्टि से प्रभाव तकः एएनआरएफ के सीईओ ने आईआईटी मंडी के दौरे पर

मंडी। आईआईटी मंडी जो भारत के प्रमुख आईआईटी संस्थानों में से एक है, ने देश के शोध परिदृश्य को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की, जब डा. शिव कुमार कल्याणरामन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मंडी दौरे पर पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य संस्थागत शोध क्षमता को सुदृढ़ करना, बहुविषयक सहयोग को बढ़ावा देना तथा एएनआरफ के शोध अनुदान एवं नवाचार कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना था, ताकि सार्थक एवं प्रभावी शोध परिणाम सामने आ सकें। एएनआरफ के प्रमुख का स्वागत करते हुए प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा निदेशक आईआईटी मंडी ने कहा कि एएनआरफ की पहलें भारत में टिकाऊ शोध वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी बहुविषयक शोध और नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में लगातार अग्रसर है।

डीएवी स्कूल में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए विद्यारंभ संस्कार का आयोजन

एजेंसी (हि.स.)

मंडी

डीएवी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर मंडी पाठशाला ईईडीपी में शनिवार को सभी नर्सरी और एलकेजी के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे आदरणीय के. एस. गुलरिया ने अपनी धर्मपत्नी वंदना गुलरिया के साथ की।

उन्होंने नन्हे बच्चों की सराहना करते हुए उन पर अपना स्नेह और आशीर्वाद सप्रेम बरसाया। परिसर में अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण के बीच नन्हे बच्चों का मंत्रोच्चार, पूजा-अर्चना के साथ स्वागत किया गया, इस संस्कार का उद्देश्य बच्चों की औपचारिक शिक्षा यात्रा को आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करना था। वेद मित्र शास्त्री ने संस्कारों का महत्व बताकर इस संस्कार को मानव जीवन में 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार बताया। पंडित की देखरेख में शिक्षिकाओं के सहयोग से बच्चों ने कलम व स्याही से

तख्ती पर ॐ लिखकर ज्ञान की शुरूआत की। उसके पश्चात हवन की विधि पूर्ण की गयी। अभिभावकों की उपस्थिति ने समारोह को और भी गरिमामय बना दिया। पाठशाला परिसर में सकारात्मक ऊर्जा, संस्कृति और संस्कार का अद्भुत संगम देखने को मिला।

प्रधानाचार्य के ऐस गुलेरिया ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यारंभ केवल शिक्षा की शुरूआत नहीं, बल्कि जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है। हम बच्चों को केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कार, अनुशासन और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने का संकल्प लेते हैं। आज का यह संस्कार कार्यक्रम बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।

सिरमौर बिजली बोर्ड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की मांग, जल्द दिए जाएं मेडिकल भत्ते

एजेंसी (हि.स.)

नाहन

सिरमौर जिला बिजली बोर्ड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की शानिवार शुभकामनाएं नाहन में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लंबित एरियर जोकि 13 फीसदी है उसकी अदायगी अभी तक नहीं की गई है और साथ ही मेडीकल बिलों की अदायगी का भी विषय अहम रहे। एसोसिएशन के महासचिव कमलेश पुंडीर ने बताया कि बिजली बोर्ड पेंशनर मेडिकल बिलों की अदायगी न होने से परेशान है। बुढ़ापे में कई बीमारियों के लगने की संभावना रहती है और और ऐसे में उनके मेडिकल बिलों का भुगतान न होने से वो लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अभी आदेश जारी किए हैं कि क्रिटिकल बीमारी वाले पेंशनरों को मासिक आधार पर मेडिकल बिलों की अदायगी हो, लेकिन अभी ये आदेश उन तक नहीं पहुंचे है यदि ऐसा है तो यह स्वागत योग्य है। इसके इलावा उनके 13 प्रतिशत की दर से एरियर लंबित पड़े हैं उनका भी जल्द अदायगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसोसिएशन की मांग है कि बिजली बोर्ड के कर्मियों को भी ओपीएस में लाया जाए ताकि वो भी पेंशन के हकदार हो सके।

मौसम 16 और 17 अप्रैल को फिर से मौसम खराब होने के आसार

हिमाचल में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, पांच जिलों में अलर्ट

एजेंसी (हि.स.)

शिमला

हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है, जबकि शिमला और मनाली सहित कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज पांच जिलों शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चम्बा और मंडी में आंधी सहित खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। कल रविवार को भी मौसम खराब रहने की संभावना तो है, लेकिन इसके लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं 13 से 15 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि 16 और 17 अप्रैल को फिर से मौसम खराब होने के आसार हैं और 16 अप्रैल को अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के जनजातीय जिलों लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी-भरमौर की पर्वत श्रृंखलाओं में हल्की बर्फबारी हो रही है। अन्य कई स्थानों पर बादलों का डेरा बना हुआ है। हमीरपुर में आज सुबह हल्की वर्षा भी हुई। निचले क्षेत्रों में अभी तक गर्मी का असर देखने को नहीं मिल रहा है। इससे लोगों को राहत तो है, लेकिन अप्रैल में ठंड के बने रहने से लोग हैरान हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। शनिवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर 11.9 डिग्री, भुंतर 9.6 डिग्री, कल्पा 2.4 डिग्री, ऊना 12.6 डिग्री, नाहन 10.3 डिग्री, पालमपुर 11.0 डिग्री, सोलन 10.5 डिग्री, मनाली 5.2 डिग्री, कांगड़ा 13.6 डिग्री, मंडी 13.3 डिग्री, बिलासपुर 14.0 डिग्री, जुब्बड़हट्टी दर्ज किया गया।

शनिवार शाम को जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाः मौसम विभाग

जम्मू। श्रीनगर मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार दोपहर या शाम के समय जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कुछ स्थानों पर मुख्य रूप से दोपहर या शाम के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश हो सकती है। 12 अप्रैल को मौसम अधिकतर शुष्क रहने की संभावना है, केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अधिकारी ने आगे बताया कि 13 और 14 अप्रैल को आसमान साफ रहने का अनुमान है जबकि 16 और 17 अप्रैल को छिटपुट और गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को कृषि कार्य फिर से शुरू करने की सलाह दी है क्योंकि अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है। इस बीच स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता फैजान आरिफ ने मौसम की संभावित गतिविधि के कारण बाग मालिकों को 11 अप्रैल को कीटनाशक छिड़काव न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को कुछ छिटपुट स्थानों को छोड़कर अधिकतर मौसम शुष्क रहने की संभावना है और सुबह के समय छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि 13 से 15 अप्रैल तक पूरे क्षेत्र में शुष्क मौसम रहने की संभावना है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा मुद्रक प्रवीन तोमर की इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22 और 49, ग्राउंड फ्लोर, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, पंचकूला-134115 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 180 ए, सेक्टर 19 सी, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पंचकूला, हरियाणा-134113 से प्रकाशित।
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय पंचकूला होगा।
स्थानीय कार्यालय
180 ए, सेक्टर 19 सी, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पंचकूला, हरियाणा-134113
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpanharyana@gmail.com

प्रदेश को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्धः नायब सिंह सैनी

बाबैन में खुलेगा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 13.38 करोड़ की लागत से मथाना-बाबैन मार्ग को किया जाए 7 मीटर चौड़ाः सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता

कुरुक्षेत्र

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार महात्मा ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं पर चलते हुए प्रदेश को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन और उनके विचार हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जो समानता, न्याय और भाईचारे पर आधारित हो। मुख्यमंत्री शनिवार को कुरुक्षेत्र के बाबैन में सैनी सभा, कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह एवं सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के शिलान्यास के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा रखी सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोले जाने की मांग को पूरा करने तथा स्वैच्छिक कोष से 51 लाख रुपये संस्था को देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से मथाना-बाबैन मार्ग को 5.5 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर चौड़ा करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम के आयोजक एवं सैनी सभा कुरुक्षेत्र के प्रधान गुरनाम सिंह सैनी ने इन मांगों के अलावा जो मुख्यमंत्री के समक्ष मांग पत्र रखा, उन्हें भी पूरा करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया। वहीं, हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने स्वयं तथा कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी की तरफ से 11-11 लाख रुपये संस्था को देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह हर्ष और गौरव की बात है कि आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने अपने विचारों, अपने संघर्षों और अपने कर्मों से भारत के सामाजिक इतिहास को नई दिशा दी। इस पावन अवसर पर मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। यह राज्यस्तरीय समारोह सामाजिक जागरण, शिक्षा और समानता के उस संकल्प को पुनर्जीवित करने का अवसर है, जिसे महात्मा फुले जी ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। ऐसे महापुरुषों, संतों और महात्माओं के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए सरकार उनकी जयंती राज्य स्तर पर मनाती है। इसके लिए सरकार ने ह्यसंत-महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजनाह्ल चलाई हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स की आधारशिला भी रखी गई है। शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का जो सपना महात्मा फुले ने देखा था, यह संस्थान उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यहां से निकलने वाले विद्यार्थी समाज के जिम्मेदार नागरिक बनकर, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। उन्होंने सैनी शिक्षा समिति के समाज के उत्थान के लिए निरंतर किए जा रहे कार्य की सराहना भी की।

उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन उस दौर में एक क्रांति की तरह था, जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय समाज में अनेक कुरीतियों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का प्रचलन था। उन्होंने इन कुरीतियों को पहचाना और उनके खिलाफ डटकर संघर्ष किया। बाल विवाह, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और महिलाओं की अशिक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने जो आवाज उठाई, वह उस समय किसी साहसिक क्रांति से कम नहीं थी। उन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि समाज में बदलाव केवल विचारों से नहीं आता, बल्कि साहस और निरंतर प्रयासों से आता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी शिक्षा में उनका अटूट विश्वास। उनका मानना था कि यदि समाज को बदलना है, तो सबसे पहले शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचाना होगा। यही कारण था कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। यह केवल एक स्कूल नहीं था, बल्कि यह उस समय के सामाजिक अंधकार के खिलाफ जलाया गया एक दीपक था। आज जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में ह्यबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओह्ल जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह महात्मा फुले जी के उस विचार का ही विस्तार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनी समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। इस समाज ने हमेशा मेहनत, ईमानदारी और सेवा को अपना धर्म माना है। कृषि, बागवानी और समाज सेवा के क्षेत्र में इस समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महान व्यक्तित्व इस समाज की धरोहर हैं, जिन्होंने पूरे देश को दिशा दी। इसी प्रकार, संत लिखमीदास, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी, बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी तथा चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद सैनी जैसे कलाकार भी इसी समाज की देन हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज का बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के सेनानी सरदार महंगा सिंह सैनी व अजीत सिंह सैनी तथा हरि सिंह सैनी जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी इसी समाज ने दिए हैं। यह परंपरा आज भी जारी है।

इस मौके पर हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी, मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, पूर्व सांसद गुरदयाल सैनी, पूर्व मंत्री बलबीर सैनी, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, चेयरमैन धर्मवीर डागर, राज्य सूचना आयुक्त परमवीर सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष तिजेंद्र सिंह गोल्डी, पूर्व विधायक डा. पवन सैनी, मेयर कोमल सैनी, प्रवक्ता जवाहर सैनी, चेयरमैन जसविंदर सिंह जस्सी, सैनी शिक्षा समिति के प्रधान नायब पटाक माजरा, वरिष्ठ उप प्रधान गुरमीत सैनी, कौशल सैनी, डिंपल सैनी, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा, मंडल अध्यक्ष शिव गुप्ता, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, महामंत्री अवतार सैनी, चेयरपर्सन कमलेश सैनी, अमरजीत सिंह ह्यबब्बू ह्य, उद्योगपति प्रदीप सैनी पिहोवा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी देंः रणबीर गंगवा

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

कैबिनेट मंत्री ने हिसार के खरड़ अलीपुर में बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा का किया अनावरण

हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण कर देश को एक सशक्त लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। उन्होंने समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन हमें समानता, न्याय और शिक्षा का महत्व सिखाता है। लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने यह बात शनिवार को हिसार के गांव खरड़ अलीपुर में बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने के उपरांत सम्बोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का दिया गया मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज भी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार महापुरुषों की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में महापुरुषों की जयंती बड़े स्तर पर मनाई जा रही है, ताकि नई पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास कार्य करना ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देना है। कैबिनेट मंत्री ने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी दें, ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

डॉ. सुमिता मिश्रा ने सरकारी अस्पतालों में तुरंत सुधार के दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों के व्यापक सुधार के आदेश दिए हैं। इसके तहत जिला अस्पतालों से लेकर राज्य के दूर-दराज के कोने में स्थित अंतिम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक स्वास्थ्य प्रणाली के हर स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं। संदेश साफ है- सख्ती से पालन और समय पर सुधार जरूरी हैं, ऑप्शनल नहीं।

डॉ. मिश्रा ने सभी जिला उपायुक्त, सिविल सर्जन, सरकारी मेडिकल कॉलेज के निदेशक और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को भेजे एक पत्र में कहा है कि लापरवाही, देरी या टालमटोल करने पर तुरंत प्रशासनिक एक्शन लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सुधार की पहल के तहत, 13 अप्रैल से सभी सरकारी अस्पतालों में एक हफ़्ते का सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अस्पताल परिसर, जिसमें वार्ड, कॉरिडोर, पार्क और आस-पास के इलाके शामिल हैं, की अच्छी तरह से सफाई करें, साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट का सही मैनेजमेंट भी करें। पारदर्शिता और निगरानी करने के लिए तय अधिकारियों को सफाई की एक्टिविटी के फोटोग्राफिक सबूत देने होंगे, जिससे रियल-टाइम अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि प्रोफेशनलिज्म और मरीजों का भरोसा बढ़ाने के लिए अस्पताल के सभी स्टाफ-मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक को ड्यूटी के दौरान तय यूनिफॉर्म पहनने और पहचान और पद साफ-साफ दिखाने का निर्देश दिया गया है। इस कदम से मरीजों के साथ बातचीत और संस्थागत अनुशासन में सुधार होने की उम्मीद है।

सरकार ने मरीजों के अनुभव को बेहतर बनाने पर बहुत जोर दिया है। अस्पतालों को यह पक्का करना चाहिए कि मरीजों और उनके अटेंडेंट के लिए साफ टॉयलेट, पीने का साफ पानी, साफ बिस्तर और बैठने की सही व्यवस्था जैसी जरूरी सुविधाएँ मौजूद हों।

इसके अलावा, संस्थागत को प्रभावी क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मरीजों के आने-जाने को आसान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इंतजार का समय कम करने और भीड़ कम करने के लिए जहाँ भी जरूरत हो, वहाँ और रजिस्ट्रेशन काउंटर और हेल्प डेस्क बनाए जाएँगे।

सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे आयुष्मान भारत हेल्प डेस्क को बिना किसी रुकावट के काम करने दें, ताकि योग्य लाभार्थियों को बिना किसी प्रक्रिया में देरी के समय पर मदद मिल सके। इसके साथ ही, एम्बुलेंस सर्विस चौबीसों घंटे पूरी तरह चालू रहनी चाहिए और सरकार इमरजेंसी में किसी भी रुकावट के लिए जीरो-टॉलरेंस अप्रोच अपनाए।

उन्होंने कहा कि मां और बच्चे की हेल्थ की अहमियत को समझते हुए, सरकार ने अस्पतालों को मैटरनिटी और बच्चों के वार्ड को अपग्रेड करने का निर्देश दिया है। लोकल संस्थाओं के साथ मिलकर, सुखदायक रंगों से दोबारा पेंट करके और बच्चों के लिए सही आर्टवर्क लगाकर, ज्यादा स्वागत करने वाला और स्ट्रेस-फ्री माहौल बनाने के लिए जगहों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

संक्षिप्त-समाचार

तीन दिवसीय सम्मेलन कुरुक्षेत्रः थ्रू द एजेस ने इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म को वैश्विक मंच पर दी नई पहचान

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में सीनेट हॉल में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ह्लकुरुक्षेत्रः थ्रू द एजेसह्ल ने इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और अकादमिक शोध के समन्वय का एक भव्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कुरुक्षेत्र की बहुआयामी विरासत को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से स्थापित किया। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययन केंद्र, स्वदेशी शोध संस्थान, जियो गीता तथा विजन कुरुक्षेत्र के सहयोग से आयोजित इस संगोष्ठी में देश-विदेश से लगभग 900 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से बड़ी संख्या में विद्वानों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी करते हुए कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक आयामों पर गंभीर विचार-विमर्श किया। सम्मेलन निदेशक प्रो. भगत सिंह ने बताया कि तीन दिनों तक चले इस सम्मेलन में 24 से अधिक अकादमिक सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें 400 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इन सत्रों में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, संस्कृत वाङ्मय, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, विधि अध्ययन तथा पंजाबी भाषा-साहित्य जैसे विविध विषयों को समाहित किया गया, जिससे यह संगोष्ठी बहुविषयी संवाद का एक सशक्त मंच बनकर उभरी। समापन सत्र में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ उसे आधुनिक तकनीकों और वैश्विक मंचों के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि इस दिशा में संगठित प्रयास किए जाएं, तो कुरुक्षेत्र भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और शोध केंद्र के रूप में स्थापित हो सकता है। प्रो. भगत सिंह ने कहा कि कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में आयोजित समग्र रूप से यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केवल एक अकादमिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को पुनः समझने, उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने और वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त और दूरगामी पहल साबित हुआ।

परिवर्तनशील मौसम को लेकर सब्जियों की खेती पर कृषि वैज्ञानिकों प्रोफेसर एसके मल्होत्रा तथा डा. सीबी सिंह के बीच हुई चर्चा

कुरुक्षेत्र। मौसम के बार बार परिवर्तनशील रहने तथा बरसात व तापमान में बदलाव का सीधा असर सब्जियों की खेती सहित अन्य फसलों पर भी पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिक डा. सीबी सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल (हरियाणा) के कुलपति प्रोफेसर एसके मल्होत्रा के साथ उनकी परिवर्तनशील मौसम को लेकर सब्जियों की खेती पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके मल्होत्रा ने परिवर्तनशील मौसम के कारण सब्जियों की खेती पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों और उनके समाधानों पर विस्तृत चर्चा की। इस चर्चा के दौरान शोध और क्षेत्रीय चुनौतियों पर मंथन किया गया। डा. सिंह ने कहा कि परिवर्तनशील मौसम का सब्जियों पर विशेषकर प्रभाव होता है। बढ़ते तापमान, बेमौसमी बारिश और मानसून में बदलाव के कारण सब्जियों में टमाटर, प्याज, मिर्च के उत्पादन में भारी गिरावट आती है। अत्यधिक गर्मी के कारण भी फसलों की वृद्धि रुक जाती है और वे जल्दी मुरझा जाती हैं। इस मौके पर कुलपति प्रो. एसके मल्होत्रा और वैज्ञानिक डा. सीबी सिंह ने कहा कि बदलते मौसम के कारण हानिकारक कीटों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे फसल प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। जलवायु-अनुकूल किस्मों को लेकर सुझाव दिया गया। प्रो. मल्होत्रा ने जोर दिया कि शोध के माध्यम से ऐसी किस्में विकसित की जाएं जो उच्च तापमान, सूखा और लवणता को सहन कर सकें। संरक्षित खेती के लिए पॉलीहाउस और नेट हाउस तकनीक का उपयोग करने की सलाह दी गई, ताकि सब्जियों को बाहरी मौसम के प्रकोप से बचाया जा सके। डा. सिंह ने कहा कि ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करके पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी अच्छी पैदावार सुनिश्चित करनी चाहिए।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा : आरती सिंह राव

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ₹नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023₹ को लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। इसको लागू करने के लिए आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस अधिनियम के प्रति जनजागरूकता लाने के लिए आज 11 अप्रैल से अभियान शुरू किया गया है , यह अभियान 20 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चलेगा जिसमें महिलाओं व आम जनमानस को अधिनियम की जानकारी देने और उनसे जुड़ाव बढ़ाने की तैयारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री आज पंचकूला में इस अभियान की शुरूआत करने के बाद मीडिया से बात कर रही थी।

आरती सिंह राव ने ₹नारी शक्ति वंदन अधिनियम₹ की जानकारी एवं इसके लाभ गिनवाते हुए बताया कि इस अधिनियम से महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन है, जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे महिलाओं को नीति निर्माण में अधिक भागीदारी का अवसर मिलेगा और लोकतंत्र और मजबूत होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में महिलाओं की मतदान में भागीदारी लगातार बढ़ रही है और कई स्थानों पर यह पुरुषों से भी अधिक है। इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है, जिसे यह अधिनियम संतुलित करेगा। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है, तो शासन अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बनता है। पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका उदाहरण है।

हरियाणा में शिक्षा गुणवत्ता सुधार को नई गतिः पीएम श्री विद्यालयों व मॉडल संस्कृति स्कूलों के बीच राज्य स्तरीय प्रतियोगिता

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

20 अप्रैल तक जिला स्तर पर चयन, अगस्त में अंतिम मूल्यांकन; स्वतंत्रता दिवस पर श्रेष्ठ विद्यालय होंगे सम्मानित

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ एवं परिणाममुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पीएम श्री विद्यालयों और वरिष्ठ माध्यमिक मॉडल संस्कृति स्कूलों के बीच राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी उपायुक्तों एवं मंडल आयुक्तों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह पहल विद्यालयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगी तथा उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने और उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में हरियाणा में 250 पीएम श्री विद्यालय तथा 218 वरिष्ठ माध्यमिक मॉडल संस्कृति विद्यालय संचालित हैं, जिन्हें गुणवत्ता एवं मूल्य आधारित शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक जिले में उपायुक्त 20 अप्रैल 2026 तक तीन पीएम श्री विद्यालय तथा तीन वरिष्ठ माध्यमिक मॉडल संस्कृति विद्यालयों का चयन करेंगे। इसके पश्चात मंडल आयुक्त 30 अप्रैल 2026 तक चयनित विद्यालयों में से शीर्ष 50 प्रतिशत विद्यालयों को अगले चरण के लिए चिन्हित करेंगे। चयनित विद्यालय 1 मई से 31 जुलाई 2026 तक विशेष सुधार चरण में भाग लेंगे। इस अवधि में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, नवीन शिक्षण पद्धतियों के समावेश, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के विस्तार तथा समग्र विद्यालय प्रबंधन को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिलों में तैनात वरिष्ठ अधिकारी संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि अंतिम मूल्यांकन 1 अगस्त से 7 अगस्त 2026 के बीच निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसके उपरांत पूरे प्रदेश से तीन सर्वश्रेष्ठ पीएम श्री विद्यालय तथा तीन सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ माध्यमिक मॉडल संस्कृति विद्यालयों का चयन किया जाएगा। विजेता विद्यालयों को वर्ष 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

कृषि मंत्री जिला हांसी के गांव बांस की अनाज मंडी में किसानों के बीच पहुंचे, एमएसपी पर गेहूं का दाना-दाना खरीदने का दिया आश्वासन

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा के आश्वासन के बाद धरना स्थल से उठे किसान

हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा आज जिला हांसी स्थित बांस गांव की अनाज मंडी पहुंचे, जहां मंडी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं।

किसानों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार गेहूं की फसल का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पर खरीदने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की सभी मंडियों में खरीद प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। मंडियों में किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उनकी उपज की बिक्री निर्बाध रूप से हो सके। श्री राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं मंडियों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। उनके निर्देशों के पश्चात प्रदेश भर में गेहूं की खरीद और उठान (लिफ्टिंग) कार्य में तेजी लाई गई है, जिससे किसानों को समय पर राहत मिल रही है। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबैन अनाज मंडी में पहुंचकर लिया गेहूं खरीद प्रक्रिया का जायजा

खरीद प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित तथा किसान हितैषी बनाने के लिए प्रदेश में लागू की हैं कई नई पहलेंः सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता

बाबैन

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में खरीद प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित तथा किसान हितैषी बनाने के लिए कई नई पहलें लागू की हैं। इन उपायों से फसल खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगेगी तथा किसानों को सुविधाजनक और तेज सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन-स्तरीय फसल सत्यापन प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत खरीद केंद्रों पर लाई गई फसल का किसान द्वारा पंजीकृत फसल से मिलान सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे फसल सत्यापन प्रक्रिया अधिक सटीक और विश्वसनीय बन रही है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को बाबैन अनाज मंडी में गेहूं खरीद प्रक्रिया का जायजा ले रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा सुमन सैनी का अनाज मंडी बाबैन में पहुंचने पर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से मंडी में गेहूं लेकर आने, विक्रय करने और पेमेंट सहित अन्य दिक्कतों के बारे में बातचीत की। किसानों ने प्रदेश सरकार की योजना की खूब तारीफ की और कहा कि जब वो मंडी में गेहूं लेकर पहुंचे तो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सामने गेहूं बेचने वाले हमीदपुर निवासी किसान धर्मचंद को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री मंडी में स्थित पूर्व चेयरमैन डिम्पल सैनी की दुकान पर भी पहुंचे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और सुव्यवस्थित ढंग से खरीद कार्य को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है तथा सभी फसलों की खरीद सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की फसल के एक-एक दाने की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने खरीद प्रणाली में व्यापक सुधार लागू किए हैं तथा प्रत्येक मंडी में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों की मंडियों की नियमित निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उपायुक्तों को जिला स्तर पर खरीद व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है। मंत्री और विधायक भी लगातार मंडियों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

केवल वाहन की फोटो के आधार पर भी गेट पास जारी करने की दी अनुमति

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खरीद प्रक्रिया में किसान की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 नामांकित व्यक्तियों को भी बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि मंडियों में माल की ट्रेसबिलिटी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एंट्री गेट पास जारी करते समय वाहन नंबर और वाहन/लोड की फोटो दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। हालांकि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुत पुराने या नए वाहनों के मामलों में, जहां वाहन नंबर उपलब्ध नहीं होता, वहां केवल वाहन की फोटो के आधार पर भी गेट पास जारी करने की अनुमति दी गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की इन तकनीक-आधारित पहलों से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में गत 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जा रही है। किसानों को 2 हजार 585 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से भुगतान भी डी.बी.टी के माध्यम से उनके बैंक खातों में साथ-साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों और गोदामों को जियो-फेंसिंग के दायरे में लाया गया है। इससे अनधिकृत उपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी और लोकेशन आधारित निगरानी प्रणाली और मजबूत होगी।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन, एसडीएम अनुभव मेहता, चेयरमैन जसविंद्र सिंह, जयभगवान शर्मा डीडी, प्रदेश सचिव राहुल राणा, प्रधान जितेंद्र खैरा, मार्केट कमेटी सचिव गुरमीत सिंह, एएफएसओ बृज मोहन, सरपंच संजीव गोल्डी ,अमरजीत सिंह ह्यबब्बू ह्यसहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

संपादकीय

लोकतंत्र की नई शक्ति के रूप में उभरतीं महिला मतदाता: केरल, असम और पुदुचेरी में ऐतिहासिक महिला मतदान

9 अप्रैल 2026 को जब केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हुआ, तो उस दिन केवल वोट नहीं पड़े – बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। इस बार की सबसे बड़ी और सबसे अर्थपूर्ण बात यह रही कि तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में महिला मतदाताओं ने न केवल पुरुषों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों में अब तक का सर्वाधिक महिला मतदान प्रतिशत भी दर्ज किया। असम में महिलाओं की मतदान भागीदारी 86.50 प्रतिशत रही, जो पुरुषों के 85.33 प्रतिशत से अधिक थी। इससे राज्य का कुल मतदान प्रतिशत 85.91 तक पहुँचा, जो 2016 के विधानसभा चुनावों के पिछले सर्वोच्च आंकड़े को पार कर गया। पुदुचेरी में महिलाओं की मतदान भागीदारी 91.40 प्रतिशत रही, जो पुरुषों के 88.13 प्रतिशत से काफी अधिक थी। केरल में महिला मतदाताओं ने 81.19 प्रतिशत की भागीदारी दर्ज की, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 75.19 रहा। केरल में यह आंकड़ा 1987 के विधानसभा चुनाव के 80.58 प्रतिशत के दशकों पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ गया। ये संख्याएँ केवल आँकड़े नहीं हैं। ये उस बदलाव का प्रमाण हैं जो भारत की आधी आबादी के भीतर पिछले कुछ दशकों में चुपचाप, लेकिन दृढ़ता से आकार लेता रहा है। वह महिला जो कभी घर की चौखट तक सीमित मानी जाती थी, आज मतदान केंद्र पर सबसे पहले पहुँचने वाली बन रही है। यह बदलाव राजनीतिक चेतना का है, आत्मसम्मान का है, और उस आत्मविश्वास का है जो शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक जागरूकता के मेल से पैदा होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस ऐतिहासिक मतदान को न केवल भारत, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक विश्व के लिए एक मिसाल और वास्तव में, जब किसी देश की महिलाएँ इस उत्साह और संकल्प के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं, तो यह सन्देश दुनिया भर के उन समाजों को भी जाता है जहाँ आज भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। पुदुचेरी ने लगभग 90 प्रतिशत का कुल मतदान प्रतिशत दर्ज किया, जबकि असम ने भी अपना अब तक का सर्वोच्च मतदान प्रतिशत हासिल किया। इन उपलब्धियों में महिलाओं की भूमिका केंद्रीय रही। यह महज संयोग नहीं है। जब महिलाएँ बड़ी संख्या में मतदान करती हैं, तो समग्र लोकतांत्रिक भागीदारी स्वतः ऊपर उठती है। यह एक सिद्ध सत्य है। लेकिन इस ऐतिहासिक उपलब्धि को केवल आँकड़ों तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। इसके पीछे के कारणों को भी समझना जरूरी है। सबसे पहली बात – महिलाओं में शिक्षा का विस्तार। केरल जैसा राज्य, जहाँ साक्षरता दर देश में सर्वाधिक है, वहाँ महिलाएँ दशकों से जागरूक और सक्रिय मतदाता रही हैं। असम में भी पिछले कुछ वर्षों में बालिका शिक्षा, महिला स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं ने महिलाओं को घर से बाहर निकालकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा है। पुदुचेरी की उच्च महिला मतदान दर इस बात का संकेत है कि छोटे क्षेत्रों में भी लोकतांत्रिक चेतना गहरी जड़ें पकड़ रही है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है – सरकारी योजनाओं का सीधा असर। चाहे वह गैस सिलेंडर की सब्सिडी हो, आवास योजना हो, महिला सुरक्षा से जुड़े कानून हों, या स्वास्थ्य बीमा – इन सब योजनाओं ने महिलाओं को यह एहसास कराया है कि सरकार कौन बनती है, इसका सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वे अब अपने वोट को हल्के में नहीं लेतीं। तीसरा कारण है – चुनाव आयोग की सक्रियता। इस बार चुनाव आयोग ने कई मतदाता-अनुकूल पहल की, जैसे उम्मीदवारों की पहचान योग्य रंगीन तस्वीरें ईवीएम बैलेट पेपर पर लगाना, मोबाइल डिपॉजिट सुविधा, नए डिजाइन के मतदाता सूचना पर्ची, और प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाताओं की सीमा। इन कदमों ने खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए मतदान को और सुगम बनाया। इसके अतिरिक्त, पहली बार असम, केरल और पुदुचेरी के सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत लाइव वेबकास्टिंग सुनिश्चित की गई। इससे पारदर्शिता बढ़ी और महिला मतदाताओं में सुरक्षा का भाव और मजबूत हुआ। चौथा और शायद सबसे गहरा कारण है – महिलाओं की बदलती मानसिकता। अब महिलाएँ यह नहीं पूछतीं कि उन्हें किसे वोट देना चाहिए, बल्कि वे स्वयं तय करती हैं। वे अपने परिवार, अपने गाँव, अपने शहर और अपने देश के भविष्य को लेकर सोचती हैं। वे राजनीतिक दलों के घोषणापत्र पढ़ती हैं, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जाँचती हैं, और सोच-समझकर निर्णय लेती हैं। यह बदलाव लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण है। अब सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक मतदान का राजनीतिक अर्थ क्या है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस चुनाव को असम के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ बताया। कांग्रेस ने कहा कि यह जनता की बदलाव की चाहत को दशार्ता है। केरल में वाम और कांग्रेस दोनों ने उच्च मतदान को अपने-अपने पक्ष में बताने की कोशिश की। लेकिन सच यह है कि जब महिलाएँ इतनी बड़ी संख्या में मतदान करती हैं, तो परिणाम अप्रत्याशित और जटिल हो जाते हैं – क्योंकि महिला मतदाता एकजुट नहीं होती, वे विविध होती हैं। उनके वोट जाति, धर्म, क्षेत्र और वर्ग की सीमाओं को पार करते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दलों को अब महिला मतदाताओं को केवल एक 'वोट बैंक' के रूप में नहीं, बल्कि एक जागरूक, स्वतंत्र और निर्णायक शक्ति के रूप में देखना होगा। उन्हें ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जो महिलाओं की वास्तविक जरूरतों – सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन – को संबोधित करें। महज चुनावी वादे अब काम नहीं आते। केरल, असम और पुदुचेरी की महिलाओं ने जो संदेश दिया है, वह पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि लोकतंत्र तब सही मायनों में मजबूत होता है, जब उसमें समाज का हर वर्ग – खासकर महिलाएँ – बराबरी से भागीदार हो। मतदान केंद्रों पर दिखी लंबी कतारें, महिलाओं के चेहरों पर उत्साह और संकल्प की चमक – यह भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत है। अंत में, यह कहना उचित होगा कि इन तीन राज्यों का ऐतिहासिक महिला मतदान केवल एक चुनावी घटना नहीं है – यह एक सामाजिक क्रांति की आहट है। जब देश की आधी आबादी इतनी जागरूकता और आत्मविश्वास के साथ अपनी राजनीतिक भूमिका निभाती है, तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, समाज के लिए प्रेरणा है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। भारत की महिलाएँ अब केवल वोट नहीं दे रहीं – वे इतिहास लिख रही हैं।

भविष्य का अमृत ईंधन है 'थोरियम'

डॉ. नुपूर निखिल देशकर (हि.स)

तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र से हाल ही में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ने भारत की ऊर्जा यात्रा को नई दिशा दी है। वैज्ञानिकों ने परमाणु अभिक्रिया की संतुलित अवस्था, जिसे 'क्रिटिकैलिटी' कहा जाता है, सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली है। यह उपलब्धि एक वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता के साथ भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता के सपने की ओर एक ठोस कदम है। इस परिप्रेक्ष्य में थोरियम एक ऐसे 'भविष्य के अमृत ईंधन' के रूप में उभर रहा है, जिसे लेकर अब उम्मीद है कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी।

थोरियम की सबसे बड़ी विशेषता उसका अत्यधिक ऊर्जा घनत्व है। सामान्यतः यह माना जाता है कि एक टन थोरियम से उतनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जितनी लगभग 35 लाख टन कोयले से मिलती है। यह तुलना न केवल थोरियम की क्षमता को दशार्ती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि यदि इसका प्रभावी उपयोग किया जाए तो ऊर्जा संकट का स्थायी समाधान संभव है।

भारत की भौगोलिक संरचना इसे थोरियम के मामले में विशेष रूप से समृद्ध बनाती है। विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। केरल के अलप्पुझा और कोल्लम तट, तमिलनाडु के कन्याकुमारी और मनावलकुरिची, ओडिशा के चांदीपुर तट तथा आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय क्षेत्रों में मोनाजाइट रेत के रूप में थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह संसाधन भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में भी ला सकता है। अनुमान है कि यह भंडार हजारों वर्षों तक देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

थोरियम की इस अपार संभावना को भारत ने बहुत पहले पहचान लिया था। वर्ष 1950 में महान वैज्ञानिक डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने इस दिशा में दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने यह समझ लिया था कि भारत में यूरेनियम की सीमित उपलब्धता के कारण थोरियम ही भविष्य का विकल्प बन सकता है। हालांकि, थोरियम का सीधा उपयोग संभव नहीं है; इसे पहले यूरेनियम-233 में परिवर्तित करना पड़ता है, जो एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए डॉ. भाभा ने भारत के लिए त्रि-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की।

इस कार्यक्रम के पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ प्लूटोनियम तैयार किया जाता है। दूसरे चरण में इस प्लूटोनियम की सहायता से थोरियम को यूरेनियम-233 में परिवर्तित किया जाता है। तीसरे और अंतिम चरण में इस परिवर्तित ईंधन का उपयोग कर बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। यह एक दीर्घकालिक और वैज्ञानिक रूप से जटिल योजना थी, लेकिन इसकी सफलता भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है।

थोरियम का उपयोग केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। यह एक रेडियोधर्मी धातु है जिसका उपयोग रेडियोमेट्रिक डेटिंग में किया जाता है, जिससे चट्टानों और जीवाश्मों की आयु का निर्धारण संभव होता है। इसके अलावा, मैग्नीशियम के साथ मिश्रधातु के रूप में इसका उपयोग उच्च ताप सहनशील और मजबूत सामग्री बनाने में होता है, जो विमानन और उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी है। हालांकि, इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को अपने प्रारंभिक वर्षों में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक उदासीनता, संसाधनों की कमी और 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने इसकी गति को धीमा कर दिया। इसके अतिरिक्त, तकनीकी चुनौतियों और वैश्विक सहयोग की कमी के कारण भी यह कार्यक्रम अपेक्षित प्रगति नहीं कर सका।

इक्कीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक और गंभीर समस्या सामने आई थोरियम की तस्करी और अवैध खनन। 2004 के बाद से समुद्री तटीय क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर मोनाजाइट रेत के गायब होने की घटनाएं सामने आईं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, लाखों टन सामग्री अवैध रूप से विदेशों, विशेषकर चीन, को भेजी गई। यदि ये आरोप सत्य हैं, तो यह न केवल आर्थिक नुकसान है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। वर्तमान समय में भारत सरकार ने इस दिशा में नए सिरे से प्रयास शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में थोरियम आधारित ऊर्जा कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है। डॉ. भाभा का जो सपना दशकों पहले अधूरा रह गया था, वह अब साकार होता दिखाई दे रहा है। भारत के पास विश्व के लगभग 25 फीसद थोरियम भंडार हैं, जो इसे इस क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बना सकते हैं।

सरकार ने स्वदेशी तकनीकों के विकास पर जोर देते हुए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और उन्नत भारी जल रिएक्टर जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। इन रिएक्टरों का उद्देश्य थोरियम के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग, नीतिगत सुधार और निवेश में वृद्धि ने इस क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान की है। आज जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब थोरियम एक स्वच्छ, सुरक्षित और दीर्घकालिक विकल्प के रूप में सामने आया है। थोरियम आधारित ऊर्जा उत्पादन में रेडियोधर्मी कचरा अपेक्षाकृत कम होता है और इसकी सुरक्षा भी अधिक होती है। यही कारण है कि इसे भविष्य का 'गेम-चेंजर' ईंधन कहा जा रहा है।

अतः यह कहा जा सकता है कि थोरियम न केवल भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि यह देश को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर एक अग्रणी स्थान भी दिला सकता है। आवश्यकता है तो केवल दूरदर्शिता, पारदर्शिता और सतत प्रयासों की। यदि भारत अपने इस प्राकृतिक संसाधन का सही दिशा में उपयोग करता है, तो वह न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि विश्व को भी स्वच्छ और सतत ऊर्जा का मार्ग दिखा सकेगा।

(लेखिका प्राध्यापिका एवं स्तम्भकार हैं)

वैश्विक संकटों के बीच विश्व बैंक अकेला नहीं जो भारत की गाथा कह रहा

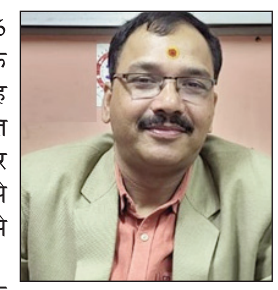
डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

इस समय पश्चिम एशिया में संघर्ष, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें विश्व अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं, पर इन सबके बीच भारत का प्रदर्शन आश्चर्यजनक रूप से संतुलित और सुदृढ़ दिखाई देता है। विश्व बैंक से लेकर तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आश्वस्त कर रही हैं कि भारत जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था और भविष्य की दृष्टि से हर चुनौती के लिए तैयार दिख रहा है, वह काबिले तारीफ है।

वस्तुतः वर्ल्ड बैंक द्वारा 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6.6 प्रतिशत तक बढ़ाना इस बात का प्रमाण है कि भारत हर परिस्थिति पर नियंत्रित करने की क्षमता रखने वाला राष्ट्र है। यहां समझनेवाली बात है कि यह इतना आसान भी नहीं है, जितना कि बाहर से किसी को दिखाई दे, क्योंकि महंगाई, ऊर्जा लागत और वैश्विक अस्थिरता जैसे खतरे सामने खड़े हैं। ऐसे मे यदि हम वर्ल्ड बैंक के अतिरिक्त अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमानों पर दृष्टि डालें, तब एक समान संदेश सामने आता है, वह है कि भारत स्थिर है, सक्षम है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी 2026 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसका मानना है कि भारत की आर्थिक संरचना इतनी मजबूत है कि वह बाहरी झटकों को सहजता से झेल सकती है, क्योंकि इसकी रीढ़ घरेलू मांग है, न कि केवल निर्यात। इसी प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाते हुए स्पष्ट किया है कि भारत का बुनियादी ढांचा निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार इसे 2026 में पूरे वर्ष भर वैश्विक संकटों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यही विचार ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के भी हैं, जोकि भारत की वृद्धि को 6.6 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत के बीच मानता है और यह रेखांकित करता है कि भारत की कर प्रणाली, श्रम सुधार और निर्यात रणनीति इसे अन्य अर्थव्यवस्थाओं से अलग बनाती है।

अब बात यहां मूडीज के साथ स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच रेटिंग्स जैसी रेटिंग एजेंसियों की भी कर लेते हैं, यह भी भारत के संदर्भ में लगभग 6.4 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि का अनुमान देती हैं। इन संस्थाओं का एकमत विश्वास इस तथ्य को पुष्ट करता है कि भारत आज के समय में सिर्फ संभावनाओं की अर्थव्यवस्था से कहीं आगे होकर अपना प्रदर्शन कर रहा है।

घरेलू मांग है भारत की सबसे बड़ी शक्ति

भारत की आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा आधार उसकी घरेलू मांग है। जब वैश्विक बाजारों में मांग घटती है, तब भी भारत के भीतर उपभोग का स्तर अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। यह एक ऐसी विशेषता है जो बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संभावित कटौती, सरकारी योजनाओं के माध्यम से आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती क्रय शक्ति ने उपभोग को निरंतर बनाए रखा है। यही कारण है कि वैश्विक मंदी का प्रभाव भारत पर सीमित रहता है। वहीं, भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में किया जा रहा निवेश आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल नेटवर्क इन सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय किया जा रहा है।

यह निवेश वर्तमान विकास को सतत बढ़ा रहा है, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि यह भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करता है। क्योंकि जब निजी निवेश अनिश्चितता के कारण धीमा पड़ता है तब सरकारी निवेश अर्थव्यवस्था को गति देने का कार्य करता है।

डिजिटल क्रांति और ऊर्जा बनी नई अर्थव्यवस्था की पहचान

भारत की डिजिटल क्रांति इन दिनों आर्थिक गतिविधियों को एक नई दिशा दे रही है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसी प्रणालियों ने आर्थिक लेन-देन को सरल और तेज बना दिया है। छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगों तक, डिजिटल तकनीक ने सभी को सशक्त बनाया है। यह परिवर्तन भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।

इसके अलावा एक कारण देश में ऊर्जा की पर्याप्तता भी है। दरअसल, पश्चिम एशिया के संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर दिया है। तेल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है। लेकिन भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। ऊर्जा स्त्रोतों का विविधीकरण, रणनीतिक भंडार का निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर, विंड) की ओर तेजी से बढ़ते कदम, वस्तुतः ये सभी प्रयास भारत को इस संकट से बचाने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

मुद्रास्फीति और संतुलन की नीति

यहां कहना यह भी होगा कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए संतुलित मौद्रिक नीति अपनाई है। जहां एक ओर ब्याज दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास की गति को भी प्रभावित नहीं होने दिया जा रहा। सरकार द्वारा लक्षित सब्सिडी प्रदान करना और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

इन्हीं तथ्यों को ओर बेहतर तरीके से पुस्तक 'द इंडिया वे' में एस. जयशंकर और गहराई से स्पष्ट करते हैं, उनका कहना है कि भारत की नीति 'रणनीतिक स्वायत्तता' पर आधारित है, यानी कि भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है और वैश्विक दबावों के अनुसार अपनी दिशा नहीं बदलता।'इंडिया सीक्स टू शेप ग्लोबल आउटकम्स, नॉट जस्ट रिएक्ट टू देम।' इसी प्रकार 'इंडिया अनबाउंड' के लेखक गुरचरण दास इस बात को रेखांकित करते हैं कि आर्थिक सुधारों ने भारत को लचीला और आत्मनिर्भर बनाया है।'इकोनॉमिक फ्रीडम हैज अनलीश्ड इंडियाज एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी।' निश्चित तौर पर यह विचार भारत की वर्तमान आर्थिक नीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा जनसंख्या बनकर उभरी है। एक विशाल कार्यबल न सिर्फ उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, यह नवाचार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करता है। वस्तुतः जब दुनिया के कई विकसित देश वृद्धावस्था की समस्या से जूझ रहे हैं, तब भारत की युवा ऊर्जा उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

कुल मिलाकर कहना यही है कि वर्ष 2026 का वैश्विक परिदृश्य भले ही आज तमाम चुनौतियों से भरा हुआ है, किंतु भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि मजबूत नीतियां, संतुलित दृष्टिकोण और दीर्घकालिक योजनाएं किसी भी संकट को अवसर में बदल सकती हैं। आज यह 6.4 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर भारत की आर्थिक क्षमता, नीति-निर्माण की दक्षता और जनता की ऊर्जा का प्रतीक बनकर हमारे सामने है।

आज का राशिफल

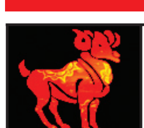
मेष: आज आपके मन में चल रहा डर या चिंता समाप्त हो सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। जीवनसाथी के प्रति सम्मान और अपनापन बढ़ेगा। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा और आप आज आपके मन में चल रहा डर या चिंता समाप्त हो सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: आज आपके कई काम तेजी से पूरे होंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ी निराशा मिल सकती है। मित्रों के व्यवहार को समझदारी से परखें। परिवार, खासकर बच्चों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: आज नए कार्यों की शुरूआत करने से बचें। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें। योग और प्राणायाम से मानसिक संतुलन बनाए रखें। रिश्तों को लेकर गंभीरता दिखाना जरूरी होगा। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: आप नए कामों की शुरूआत कर सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस से लाभ मिलने के संकेत हैं। लोग आप पर भरोसा करेंगे और यात्रा की योजना बन सकती है। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद करने से बचें। आपके सामने अच्छे अवसर हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। अनुभवी लोगों की सलाह लेना फायदेमंद होगा। बड़े भाई-बहनों को लेकर हल्की चिंता रह सकती है। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कारोबार में परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नजर आएंगी। इससे आत्मविश्वास मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में लंबी चर्चाएं हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में हल्का तनाव संभव है। *(सिटी दर्पण)*

तुला: दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अचानक कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। व्यापार में चुनौतियाँ आ सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। अहंकार से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गलत दिशा में जाने से बचें। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: रचनात्मक कार्यों में आपकी पहचान बनेगी। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी। अचानक धन लाभ के योग हैं। परिवार, खासकर बड़े भाई-बहनों से खुशी मिलेगी। दोपहर बाद कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उद्योग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। *(सिटी दर्पण)*

धनु: आप अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को समय पर पूरा कर लेंगे। संतान की उपलब्धियों से गर्व महसूस होगा। रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। जीवनसाथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। *(सिटी दर्पण)*

मकर: पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। काम धीमी गति से होंगे, लेकिन अंततः सफलता जरूर मिलेगी। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: अपनी निजी बातें दूसरों से साझा करने से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से रक्तचाप से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। खानपान और दिनचर्या को अनुशासित रखें। अधिक सोचने से बचें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। *(सिटी दर्पण)*

मीन: आज मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। परिवार के सदस्य आपसे खुश रहेंगे। परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जीवनसाथी एक अच्छे मित्र की तरह आपका साथ देगा, जिससे आप अपने मन की बातें साझा कर पाएंगे। *(सिटी दर्पण)*

सबरीमाला मंदिर पुनर्विचार में आस्था और परंपरा का ध्यान रखना जरूरी है

डॉ. निवेदिता शर्मा (हि.स)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 के सबरीमला निर्णय पर पुनर्विचार की प्रक्रिया को लेकर आज हमने यह माल लिया है कि यह भारत की सभ्यतागत चेतना, उसकी आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन खोजने का एक गंभीर प्रयास है। सबरीमाला मंदिर विवाद का मूल प्रश्न महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा अवश्य है, किंतु इसकी गहराई इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह उस बिंदु को छूता है जहां भारतीय सभ्यता की हजारों वर्षों से चली आ रही जीवंत परंपराएं आधुनिक न्यायशास्त्र के साथ संवाद करती हैं।

इससे पूर्व 2018 में दिए गए 4:1 बहुमत के निर्णय ने 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर लगी परंपरागत रोक को समाप्त कर दिया था। इसे एक वर्ग ने लैंगिक समानता की जीत के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु इस निर्णय का विरोध हुआ, यहां समझनेवाली बात यह है कि इसे लेकर पुरुषों के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी सामने आईं, जिन्होंने इस न्यायालयीन निर्णय का विरोध किया। सभी को समझना होगा कि सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में पूजा जाता है। यह एक विशिष्ट आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है।

भारतीय परंपरा में देवता का स्वरूप ही उपासना की पद्धति को निर्धारित करता है। ऐसे में यदि उस स्वरूप से जुड़ी परंपराओं में परिवर्तन किया जाता है, तब वह सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं होता है, उस देवता की अवधारणा में हस्तक्षेप के समान हो जाता है। यही कारण है कि अनेक श्रद्धालु इस मामले को समानता बनाम भेदभाव के सरल द्वंद्व के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे आस्था की अखंडता के प्रश्न के रूप में समझते हैं।

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण आयाम न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका है, विशेषकर धार्मिक मामलों में। 'अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं' का सिद्धांत, जो शिरूर मठ मामले में विकसित हुआ था, प्रारंभ में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए था, किंतु समय के साथ यह सिद्धांत न्यायालयों को यह निर्धारित करने का अधिकार देने लगा है कि किसी धर्म की मूलभूत प्रथाएं कौन-सी हैं। यह परिवर्तन चिंताजनक है, क्योंकि इससे न्यायपालिका उन क्षेत्रों में प्रवेश करने लगती है, जो मूलतः धर्मशास्त्रीय और आध्यात्मिक हैं।

याचिकाकताओं का यह तर्क महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश, चाहे कितने ही विद्वान क्यों न हों, वे सदियों पुरानी परंपराओं की आध्यात्मिक गहराई का पूर्ण आकलन नहीं कर सकते। यदि न्यायालय यह तय करने लगें कि कौन-सी प्रथा आवश्यक है और कौन-सी नहीं, तो वे आस्था के निर्णायक बन जाते हैं। यह धार्मिक स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत है, जोकि भारतीय संविधान की आत्मा में निहित है।

इस पूरे विवाद के केंद्र में एक और गहरी समस्या है, पाश्चात्य कानूनी ढांचे और भारतीय सभ्यतागत वास्तविकताओं के बीच असंगति का होना। पश्चिमी विचारधारा में धर्म को प्रायः एक संगठित, केंद्रीकृत संस्था के रूप में देखा जाता है, जहां नियम स्पष्ट और संहिताबद्ध होते हैं। उनके लिए ये धर्म सिर्फ एक रिलीजन है। ऐसे में रिलीजन के अर्थ में धर्म बहुत सीमित हो जाता है, इसके विपरीत भारत में धर्म जीवन का समग्र दर्शन है, जोकि विविधता, बहुलता और संदभार्नुकूलता पर आधारित है। यहां परंपराएं स्थानीय, जीवंत और निरंतर विकसित होती रहती हैं।

ऐसी स्थिति में यदि पश्चिमी उदारवादी अवधारणाओं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकारों की पूर्ण प्राथमिकता को भारतीय संदर्भ में बिना समुचित अनुकूलन के लागू किया जाता है तो यह स्वाभाविक रूप से टकराव उत्पन्न करता है। सबरीमाला मंदिर का निर्णय इसी टकराव का एक उदाहरण माना जा सकता है, जहां व्यक्तिगत अधिकारों को सामूहिक आध्यात्मिक परंपराओं के ऊपर प्राथमिकता दी गई।

न्यायालय को आज यह भी ध्यान देना चाहिए कि सबरीमला आंदोलन का एक उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली है। यह तथ्य उस धारणा को चुनौती देता है कि यह संघर्ष केवल महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध था। अनेक महिलाएं स्वयं इस परंपरा के पक्ष में खड़ी हुईं, क्योंकि वे इसे भेदभाव नहीं, बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा मानती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में आस्था और पहचान के प्रश्न केवल अधिकारों की भाषा में नहीं समझे जा सकते हैं।

पुनर्विचार याचिकाओं में धार्मिक स्वायत्तता की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। धार्मिक संगठनों का तर्क है कि भारतीय धर्मों को अब तक स्पष्ट कानूनी पहचान नहीं मिली है, जिसके कारण वे अपने अधिकारों की प्रभावी रक्षा नहीं कर पाते। इस स्थिति में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, जोकि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए चुनौती बन सकता है। इस संदर्भ में यह सुझाव भी महत्वपूर्ण है कि न्यायालयों को धार्मिक मामलों में विशेषज्ञों और धमार्चार्यों से परामर्श करना चाहिए। जैसे तकनीकी मामलों में विशेषज्ञों की राय ली जाती है, वैसे ही धर्म से जुड़े मामलों में भी संबंधित परंपराओं के ज्ञाताओं की सहभागिता आवश्यक है। यह दृष्टिकोण न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संतुलित और संवेदनशील बना सकता है।

केरल सरकार के रुख में आया परिवर्तन भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। पहले जहां उसने 2018 के निर्णय का समर्थन किया था, वहीं अब उसने यह स्वीकार किया है कि दीर्घकालिक परंपराओं पर निर्णय लेने से पहले धार्मिक विद्वानों से परामर्श आवश्यक है। यह बदलाव इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आस्था से जुड़े प्रश्न केवल कानूनी तर्कों के माध्यम से हल नहीं किए जा सकते। 'संवैधानिक नैतिकता' बनाम 'सामाजिक नैतिकता' का विमर्श भी इस विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संवैधानिक नैतिकता हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों की ओर उन्मुख करती है, किंतु इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक होना चाहिए। यदि इसे इस प्रकार उपयोग किया जाए कि वह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह नकार दे, तो यह एक प्रकार की न्यायिक अतिरेकता बन सकती है। वहीं, 'सामाजिक नैतिकता' का हवाला देकर हर परंपरा को बिना जांच के स्वीकार करना भी उचित नहीं है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाए। न्यायालय को यह समझना होगा कि भारतीय समाज में धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि सामूहिक पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता का आधार है।

सबरीमाला प्रकरण में प्रस्तुत उदाहरण जैसे कुछ मंदिरों में पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित होना या विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति मिलना यह दशार्ते हैं कि भारतीय धार्मिक परंपराएं अत्यंत विविध और विशिष्ट हैं। इन्हें एक समान मानक से नहीं परखा जा सकता। प्रत्येक परंपरा का अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदर्भ होता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को शानदार ढंग से मनाने के लिए श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया

श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित राज्य में पूरे साल कराए जाने वाले कार्यक्रमों में सेमिनार, कीर्तन, यात्राएं और पौधे लगाने का अभियान चलाया जाएगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित कराए जाने वाले श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया।

यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पंजाब भवन में संत समाज के साथ बैठक के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रमों और पहलकदमियों की श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की। इन कार्यक्रमों में सेमिनार, कीर्तन समागम, यात्राएं, पौधे लगाने के अभियान और 650 एकड़ में गुरु रविदास बगीचियां लगाना शामिल है तथा इस संबंध में मुख्य समागम खुरालगढ़ में होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस और श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को मनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी क्योंकि गुरु जी के संदेश को दुनिया भर तक पहुंचाना हमारा सामूहिक फर्ज है।

उन्होंने कहा, श्री गुरु रविदास महाराज जी ने हर भेदभाव से मुक्त बराबरी वाले समाज की कल्पना की थी। पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का आगामी 650वां प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर मनाया जाए। हमने हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम कराए थे।

समागम की तैयारियों का जिक्र करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने साझा किया, श्री गुरु रविदास महाराज जी के

650वें प्रकाश पर्व को शानदार ढंग से मनाने के लिए पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई है। श्री गुरु रविदास महाराज जी ने समूची मानवता की भलाई और सभी वर्गों की बराबरी का संदेश दिया और ऐसे समानतावादी समाज की नींव रखी जहां कोई भी दुखी न हो।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, हमारी सरकार श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों के आधार पर समाज की रचना के लिए प्रतिबद्ध है, जो मानवता को बराबरी की ओर निर्देशित करते रहते हैं। श्री गुरु रविदास महाराज जी गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए महान आध्यात्मिक दूत और मसीहा थे, जिन्होंने हमें नैतिक जीवन जीने की दिशा दी। यह प्रकाश पर्व ऐसे समाज के सृजन के लिए खुद को दोबारा समर्पित करने का अवसर है जहां हर व्यक्ति आत्म-सम्मान और सम्मान के साथ भेदभाव से मुक्त रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा, मैं संत समाज से अपील करता हूं कि 650वें प्रकाश पर्व के मौके पर विश्वव्यापी जश्नों के लिए मार्गदर्शन करें और सुझाव दें। यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि ये जश्न मेरे कार्यकाल के दौरान मनाए जा रहे हैं। हमारी सरकार इन कार्यक्रमों को सबसे उचित ढंग से मनाना सुनिश्चित करेगी। मैं संत समाज से कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपने सुझावों से हमारा मार्गदर्शन करने की अपील करता हूं।

पूरे साल चलने वाले जश्नों में सेमिनार और वर्कशॉप, विशेष कीर्तन समागम, तीर्थ यात्रा, स्कूल वार मुकाबले, डॉक्यूमेंट्री शो, ड्रोन शो, रक्तदान शिविर, पौधे लगाने के अभियान चलाने का फैसला किया गया है। मुख्य समागम खुरालगढ़ में करवाने का निर्णय लिया गया है। गुरु रविदास जी बगीचियों की स्थापना पूरे पंजाब में कुल 650 एकड़ पंचायती जमीन पर प्रति जिला औसतन 6.50 लाख पौधे लगाने के अभियान के साथ-साथ मैराथन, शोभा यात्राएं, साइकिल रैलियां और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से की जाएगी।

650वें प्रकाश पर्व को समर्पित मुख्य समागम में गुरु रविदास जी के जीवन पर प्रदर्शनी का उद्घाटन, कथा और कीर्तन दरबार, श्री गुरु रविदास जी के योगदान को समर्पित संत सम्मेलन, मीनार-ए-बेगमपुरा में 3डी प्रोजेक्शन, ड्रोन शो, गुरु रविदास जी की बाणी पर कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रम शामिल होंगे।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, तरुणप्रीत सिंह सौंद, लाल चंद कटारूचक्क और डॉ. रवजोत, लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, सलाहकार, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले दीपक बाली तथा अन्य भी मौजूद थे।

भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कार नीति लागू, 28 सबसे वांछित अपराधियों की सूची जारी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने एक अहम और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पुरस्कार नीति लागू की है। इस नीति के तहत पंजाब पुलिस को राज्य में वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों तथा उनके नेटवर्क के बारे में विश्वसनीय जानकारी देने वाले व्यक्तियों को इनाम देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने 28 सबसे वांछित अपराधियों की सूची भी जारी की है। गैंगस्टरों ते वार प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को 1 लाख रुपये तक, पुलिस कमिश्नर/रेंज आईजी/डीआईजी को 1.5 लाख रुपये तक, विभिन्न विंगों के प्रमुखों (स्पेशल डीजीपी/एडीजीपी) को 2 लाख रुपये तक और डीजीपी को 2 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत करने की शक्तियां प्रदान की हैं। यह राशि केवल सही और प्रमाणिक सूचना देने वाले व्यक्तियों को ही दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर पूरी तरह से लगाम लगाना है और इसके लिए जनसहभागिता को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। प्राप्त जानकारी की पहले जांच की जाएगी और तय मानकों के आधार पर ही इनाम दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं होने दिया जाएगा।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 9394693946 पर जानकारी साझा कर सकते हैं। पुलिस के अनुसार, ऐसी विश्वसनीय सूचना जिससे वांछित या घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी संभव हो सके, उस पर इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

नशीले पदार्थ और अवैध हथियार तस्करी रैकेट से जुड़े तीन व्यक्ति गिरफ्तार; 6.5 किलोग्राम हेरोइन, पिस्तौल और 1 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/बटाला

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए बटाला पुलिस ने 6.5 किलोग्राम हेरोइन, एक .30 कैलिबर पिस्तौल, छह जिंदा कारतूस और 1 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सीमा पार से संचालित नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों के तस्करी रैकेट का पदार्फाश किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान निशान सिंह निवासी मूलियांवाल (बटाला), रविपाल सिंह निवासी रायपुर और एक नाबालिग के रूप में हुई है। नशीले पदार्थ और ड्रग मनी की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने उनकी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार भी जब्त कर ली है।

यह सफलता 30 मार्च 2026 को बटाला के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हुई जबरन वसूली से संबंधित फायरिंग की घटना में गिरफ्तार आरोपियों वंश और सुखचैन उर्फ जशन से लगातार पूछताछ और मामले की गहन जांच के बाद हासिल हुई है। उल्लेखनीय है कि उनके कब्जे से दो .30 बोर पिस्तौल बरामद किए गए थे। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि नशीले पदार्थों और हथियारों की बरामदगी जबरन वसूली, ड्रग तस्करी और अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क के बीच मजबूत गठजोड़ को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हथियार नेटवर्क के भीतर काम कर रहे ऑपरेटरों को सप्लाई किए जा रहे थे। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलर के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले के आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए जांच जारी है, ताकि पूरे नेटवर्क का पदार्फाश किया जा सके। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बटाला महिताब सिंह ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी वंश और सुखचैन ने खुलासा किया था कि उन्हें संदिग्ध व्यक्तियों–एक नाबालिग और रविपाल–से हथियार प्राप्त हुए थे। उनके खुलासे के आधार पर पुलिस टीमों ने रविपाल सिंह और उसके नाबालिग साथी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जिसने हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में सहयोग करने की बात कबूल की। एसएसपी ने कहा, आरोपी रविपाल ने खुलासा किया कि उसने अपने विदेशी हैंडलर के निर्देश पर निशान सिंह को एक खेप डिलीवर की थी। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने अमृतसर के कमला देवी एवेन्यू के पास निशान सिंह की फॉर्च्यूनर कार को रोका और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 6.5 किलोग्राम हेरोइन, एक .30 कैलिबर पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और 1 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने और सजाओं को और सख्त बनाने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने आज जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 में सख्त संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता और सम्मान बनाए रखने तथा बेअदबी के दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए उम्रकैद तक का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन विधेयक सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।

यह फैसला आज यहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते समय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है और समाज में अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 298, 299 और 300 ऐसे मामलों से निपटती हैं, लेकिन इनमें दोषियों के खिलाफ कठोर सजा का पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

गहन विचार-विमर्श और व्यापक सलाह-मशवरे के बाद भगवंत सिंह मान सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता की रक्षा करने और समाज में आपसी सम्मान, भाईचारे तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है।

इन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए और धार्मिक पवित्रता तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम-2008 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रस्तावित जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026 में बेअदबी के दोषियों के लिए उम्रकैद सहित सजाओं को और कड़ा किया गया है।

यह प्रस्तावित कानून दुर्भावनापूर्ण तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और पंजाब में शांति, कानून-व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भोले-भाले घर खरीदने वालों को रियल एस्टेट डेवलपर्स की उल्लंघनाओं के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा: रीना गुप्ता

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने उन आम नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान किया है, जो कुछ हाउसिंग, रिहायशी और व्यावसायिक परियोजनाओं में प्रोजेक्ट प्रमोटरों द्वारा की गई पर्यावरण संबंधी उल्लंघनाओं के कारण सेल डीड और बिजली कनेक्शन पर लगी पाबंदियों से प्रभावित हो रहे थे।

एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप के तहत बोर्ड ने स्वीकार किया कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के कारण इन परियोजनाओं पर लगाई गई पाबंदियों से उन आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिन्हें इन उल्लंघनों की जानकारी नहीं थी और जिन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई इन परियोजनाओं में निवेश की थी। जनता से प्राप्त कई शिकायतों और मार्च 2026 में गठित वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए बोर्ड ने अब एक संतुलित और जनहितैषी दृष्टिकोण अपनाया है।

9 अप्रैल के आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रिहायशी कॉलोनियों और व्यावसायिक परियोजनाओं की सेल डीड पर प्रतिबंध आम लोगों के लिए परेशानी पैदा करेगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें किफायती आवास की आवश्यकता है।

संशोधित निर्देशों के तहत बोर्ड ने व्यक्तिगत खरीदारों के लिए सेल डीड पंजीकरण और बिजली कनेक्शन जारी करने की अनुमति दे दी है, ताकि नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकारों और आवश्यक सेवाओं से वंचित न किया जाए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि डिफॉल्ट डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जिसमें पर्यावरण कानूनों के तहत मुकदमा चलाना और पूर्ण अनुपालन तक नई स्वीकृतियों पर रोक लगाना शामिल है। बोर्ड ने आगे कहा कि बिजली तक पहुंच एक बुनियादी आवश्यकता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट प्रमोटरों की गलतियों के कारण इस तरह की आवश्यक सेवाओं से इनकार करना निर्दोष खरीदारों के लिए अनावश्यक कठिनाई पैदा कर रहा था।

पीपीसीबी की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने इस निर्णय के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पर्यावरण कानूनों का पालन लोगों के मौलिक अधिकारों और सम्मान की कीमत पर न हो। निर्दोष घर खरीदारों को उन उल्लंघनों की सजा नहीं भुगतनी चाहिए, जो उन्होंने किए ही नहीं हैं।

संक्षिप्त-समाचार

प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत 92 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने हाशिए पर मौजूद वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी की है। यह जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों से संबंधित विद्यार्थियों को यह राशि प्रदान की गई है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत राज्य भर के 92 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है, जिससे हजारों जरूरतमंद परिवारों को अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में बड़ी सहायता मिली है। इस राशि से विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम मानती है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह छात्रवृत्ति केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद विद्यार्थियों के सपनों को पंख देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल होता है और इस तरह की सहायता उनके लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आती है। मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे ये प्रयास भविष्य में सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त पंजाब की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि हाशिए पर मौजूद वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और इस दिशा में आगे भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि पंजाब सरकार शिक्षा के माध्यम से समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर जरूरतमंद विद्यार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने वृंदावन में नाव पलटने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के स्पीकर स.कुलतार सिंह संधवां ने आज वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। स्पीकर स.संधवां ने इस दुखद समाचार को सुनकर गहरा शोक प्रकट किया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए तथा इस हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ईश्वर पीड़ित परिवारों को इस दुख की घड़ी में इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

गैंगस्टरों ते वार का 81वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 516 स्थानों पर छापेमारी; 239 गिरफ्तार

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निर्णायक गैंगस्टरों ते वार के 81वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मानचित्रित 516 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका शुभारंभ 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव द्वारा किया गया था एंटी -गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं। 81वें दिन की कार्रवाई के दौरान पुलिस दलों ने 239 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान के आरंभ से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 20,395 हो गई है। इसके अतिरिक्त 72 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 69 व्यक्तियों को जांच एवं पूछताछ के उपरांत रिहा कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान 14 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। आम जन एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों एवं गैंगस्टरों के संबंध में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं साझा कर सकते हैं। इस दौरान पुलिस दलों ने नशों के विरुद्ध अपने अभियान युद्ध नशों विरुद्ध को 406वें दिन भी जारी रखते हुए आज 104 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 18 किलोग्राम गांजा, 1486 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 6750 रुपये की मादक पदार्थ संबंधी धनराशि बरामद की गई। इस प्रकार, मात्र 406 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 58,290 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने आज 33 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने एवं पुनर्वास हेतु उपचार के लिए प्रेरित किया है।

धामी ने मथुरा में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताई

जैतो। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में नाव पलटने से हुए भयानक हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताई है।एडवोकेट धामी ने कहा कि यह उन पीड़ित परिवारों के लिए बहुत दुख की बात है, जिन्होंने अपनों को खो दिया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के लिए भगवान से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति दें और उनके परिवारों को यह दुख सहने की ताकत दें।एडवोकेट धामी ने कहा कि शिरोमणि कमेटी पीड़ित परिवारों के दुख में शामिल है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी के मैनेजमेंट में मथुरा में स्थित गुरुद्वारा साहिब में बृजपाल सिंह को ड्यूटी दी गई है, जो पीड़ितों की जरूरत के हिसाब से मदद करेंगे।

मथुरा नाव हादसे में जान-माल के नुकसान पर गहरा दुख, इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मान जगराओं पहुंचकर मथुरा पीड़ित परिवारों से मिले, संकट की घड़ी में हर संभव सहायता का भरोसा

सिटी दर्पण संवाददाता
जगराओं

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जगराओं का दौरा कर मथुरा के पास नाव पलटने की दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की और संकट की इस घड़ी में हर संभव सहायता का भरोसा दिया। इस घटना में हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वृंदावन की यात्रा के दौरान यमुना नदी में पीड़ितों की नाव पलट गई, जिसमें अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं और चार लापता व्यक्तियों की तलाश जारी है।

- वृंदावन के दर्शन के लिए जाते समय नाव पलटने से हुआ हादसा, 11 शव बरामद, चार लापता व्यक्तियों की तलाश जारी
- पंजाब ने बचाव कार्यों के लिए गोताखोरों की टीम भेजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में है और बचाव कार्यों में सहायता के लिए पंजाब की ओर से गोताखोरों की टीमें पहले ही भेजी जा चुकी हैं। जवाबदेही और रोकथाम पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने और ऐसे हादसों को रोकने के लिए उन्होंने यह मुद्दा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है।

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मथुरा के पास हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कीमती जिंदगियों के नुकसान पर बेहद दुख हुआ है। मेरी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीड़ित वृंदावन में माथा टेकने जा रहे थे, तभी उन्हें ले जा रही नाव यमुना नदी में पलट गई। मुख्यमंत्री ने बताया, अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि चार लापता व्यक्तियों की तलाश अभी जारी है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से बचाव कार्यों में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की मदद के लिए घटनास्थल पर गोताखोरों की टीमें भेजी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, इस हादसे में बचे लोगों को आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में अपने समकक्ष के साथ लगातार संपर्क में हूं और चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों की निकटता से निगरानी कर रहा हूं।

रोकथाम उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि भविष्य में ऐसे पवित्र स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह जरूरी है कि संबंधित राज्य सरकारें जन महत्व के स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैं जान गंवाने वालों के परिवारों, रिश्तेदारों और मित्रों के प्रति दिल से सहानुभूति प्रकट करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पंजाब सरकार इस संकट की घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

भायंदर में आग से 50 झोपड़ियां जलीं दो किशोरों समेत तीन की दर्दनाक मौत

सिलेंडर फटने से बढ़ी आग: धमाकों से दहला इलाका

एजेंसी (हि.स.)
मुंबई/भायंदर

फोटोः हि.स.

महाराष्ट्र के भायंदर (पूर्व) स्थित इंद्रलोक फेज-4 इलाके में शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात भीषण आग लगने से कोहराम मच गया। एक आरक्षित भूखंड (रिजर्व प्लॉट) पर बसी झुग्गी-बस्ती में लगी इस भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें करीब 50 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। इस दुखद हादसे में तीन लोगों की जान चली गई है, जिनमें दो सगे भाई बताए जा रहे हैं।

हादसा शुक्रवार की देर रात उस वक्त हुआ जब बस्ती के लोग गहरी नींद में थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के कुछ ही देर बाद झोपड़ियों में रखे घरेलू गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे। सिलेंडरों में हुए सिलसिलेवार धमाकों ने आग की लपटों को और भी भयावह बना दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाके इतने जोरदार थे कि काफी दूर तक उनकी आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते पूरी बस्ती आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भायंदर फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड के जवानों ने जान जोखिम में डालकर जलते हुए झोपड़ों के बीच से अन्य सिलेंडरों को बाहर निकाला, जिससे एक और बड़ा विस्फोट टल गया। इस दौरान इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। हालांकि, आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि तीन लोग अपनी जान नहीं बचा सके। मृतकों की शिनाख्त इस प्रकार हुई है- गुड्डू राम (46 वर्ष), सूरज लियाकत अली मंडल (14 वर्ष), रोहित रहमत अली मंडल (15 वर्ष)। शनिवार सुबह तक फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, लेकिन तब तक 50 से अधिक परिवारों का आशियाना और सारा सामान खाक हो चुका था।

भायंदर पुलिस स्टेशन की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस बात की गहनता से छानबीन कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या किसी मानवीय लापरवाही के कारण। साथ ही, आरक्षित भूखंड पर इतनी बड़ी संख्या में बनी झुग्गियों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर भी स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में शोक का माहौल है और बेघर हुए लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री के बिना बोले ही संसद के पहले अधिवेशन का अंत

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

नेपाल में हुए आम निर्वाचन के बाद संसद के पहले अधिवेशन में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कोई भाषण नहीं दिया। नेपाल की संसद का पहला अधिवेशन बिना प्रधानमंत्री के भाषण के ही शनिवार से समाप्त हो गया है।

बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में जेनजी आंदोलन के बल पर हुए प्रतिनिधि सभा चुनाव के बाद करीब दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनी। ऐसे में यह जानने को लेकर व्यापक उत्सुकता थी कि प्रधानमंत्री शाह संसद के पहले अधिवेशन में क्या बोलेंगे। आमतौर पर चुनाव के बाद बनने वाले प्रधानमंत्री संसद को संबोधित करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं, मूल्यों और नीतियों की जानकारी देते हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी अतीत में यह एक स्थापित परंपरा रही है। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने शनिवार को समाप्त हुए संसद के पहले अधिवेशन के दौरान अपने ही जैसे देशभर से चुने गए सांसदों के सामने सरकार की नीति और मूल्यों को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझा। 27 मार्च को प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद बालेन्द्र शाह ने आगामी 100 दिनों में लागू किए जाने वाले प्रशासनिक सुधारों के 100 बिंदुओं वाला कार्यसूची पारित कर सार्वजनिक कर दी है। इस कार्यसूची में नए कानून बनाने और पुराने कानूनों में संशोधन जैसे कई कार्य शामिल हैं, जिनके लिए संसद का सहयोग आवश्यक होगा। इसके बावजूद, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में पारित इस कार्यसूची को संसद में पेश तक नहीं किया। इसे औपचारिक रूप से संसद के संज्ञान में भी नहीं लाया गया। परिणामस्वरूप, अन्य निर्वाचित सांसदों को भी मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से ही सरकार की 100-दिवसीय योजना और उसकी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ी। संसदीय व्यवस्था के जानकार प्रधानमंत्री के इस तरह संसद में न बोलने को हास्यास्पद मानते हैं। संघीय संसद सचिवालय के पूर्व महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई के अनुसार, आम चुनाव के बाद संसद के पहले अधिवेशन में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधन करने की परंपरा रही है। इस परंपरा के विपरीत पूरे अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के मौन रहने पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया।

नेपाल में बालेन्द्र शाह मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या 40 प्रतिशत पहुंची

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल में बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी 40 प्रतिशत तक बढ़ाकर समावेशी शासन पर जोर दिया है। बालेन्द्र शाह के मंत्रिमंडल में शामिल कुल 15 मंत्रियों में 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जो कुल 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में बने नए मंत्रिमंडल में सोविता गौतम को कानून, न्याय और संसदीय मामलों की मंत्री, गीता चौधरी को कृषि एवं पशुपालन विकास मंत्री, सीता बादी को महिला, बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिक मंत्री और निशा मेहता को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सिफारिश पर बाद में राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने शुक्रवार को ही गौरी यादव को उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री शाह की प्रेस विशेषज्ञ दीपा दाहाल ने कहा कि यह नेपाल में कैबिनेट स्तर पर महिलाओं की भागीदारी के लिए एक नया मानक स्थापित करता है। उन्होंने कहा, हवर्तमान सरकार समावेशी और समानतापूर्ण शासन के लिए प्रतिबद्ध है। 40 प्रतिशत महिला मंत्रियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि परिवर्तनकारी राजनीति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता व्यवहार में लागू हो रही है।ह नेपाल के संविधान में राज्य निकायों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की गई है, लेकिन पिछली सरकारें अक्सर इस सीमा को पूरा नहीं कर पाई थीं।

गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद विदेश से ही कानूनी परामर्श ले रहे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देउवा

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी, पूर्व विदेश मंत्री डा आरजू देउवा ने विदेश से ही कानूनी परामर्श शुरू कर दिया है। देउवा दंपत्ति इस समय स्वास्थ्य उपचार के लिए हांगकांग में हैं।

विदेश में रह रही आरजू व्हाट्सऐप के माध्यम से वकीलों से गिरफ्तारी वारंट को लेकर परामर्श ले रही हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्म बहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी समेत अन्य कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत की है। अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू होने के बाद आरजू कांग्रेस नेताओं और अपने निकटस्थ वकीलों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उनसे बातचीत करने वाले कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि वह नेपाल की स्थिति और घटनाक्रम के बारे में जानकारी ले रही हैं तथा वीडियो और टेक्स्ट संदेश भी भेज रही हैं। गिरफ्तारी वारंट के बाद नेपाल लौटने या न लौटने के बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। वारंट जारी होने के बाद देउवा दंपत्ति को फरार सूची में रखा गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता खाती ने भी पुष्टि की कि वारंट जारी होने के बाद आरजु से उनकी बातचीत हुई है। यदि वे नेपाल नहीं लौटते हैं, तो सरकार इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है। कांग्रेस के महासचिव प्रदीप पौडेल ने कहा कि देउवा दंपत्ति को नेपाल आकर जांच में सहयोग करना उपयुक्त होगा। उनके अनुसार, रेड कॉर्नर नोटिसजारी होने से पहले ही स्वदेश लौटकर जांच में सहयोग करने से अच्छा संदेश जाएगा। फरवरी महीने में विदेश गए देउवा दंपत्ति के नेपाल लौटने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। 25 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री देउवा इलाज के नाम पर सिंगापुर गए थे, जबकि आरजू देउवा 22 फरवरी को भारत गई थीं और वहीं से सिंगापुर पहुंची थीं।

अरनिया सेक्टर में मिला संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा

जम्मू। सीमा पुलिस चौकी साई सेक्टर अरनिया के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गरोरे नाले के पास सरदारी खेल मैदान में शनिवार को लगभग 06:55 बजे एक संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा देखे जाने की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। सीमा पुलिस चौकी साई की एक पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित कर लिया। हरे और सफेद रंग के इस गुब्बारे को कब्जे में ले लिया गया। बरामद वस्तु को आगे की जांच और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए सीमा पुलिस चौकी साई में रखा गया है। वस्तु के स्रोत और उद्देश्य का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस सतर्क है और जनता से आग्रह करती है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को दें।

संक्षिप्त-समाचार

मणिपुर में कुकी और नगा उग्रवादी संगठनों के बीच मुठभेड़, बीएसएफ जवान की मौत

इम्फाल। मणिपुर के उखरूल जिले में कुकी और नगा उग्रवादी संगठनों के बीच हुई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि यह घटना लिटान थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोंगकोट चेपू इलाके में हुई, जहां दोनों उग्रवादी समूहों के बीच भारी गोलीबारी हुई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ की 170वीं बटालियन के कांस्टेबल मिथुन मंडल की मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

होटल में धन उगाही के आरोप में फर्जी पत्रकार सहित तीन गिरफ्तार

गुवाहाटी। राजधानी गुवाहाटी पुलिस ने बोरागांव क्षेत्र के एक होटल में धन उगाही करने के आरोप में एक फर्जी पत्रकार और एक संगठन के नेता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया है कि तीनों आरोपित होटल से पैसे की मांग करने पहुंचे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर मौके पर ही उन्हें पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने इससे पहले भी उसी होटल से दो किस्तों में 20 हजार रुपये वसूल किए थे। पुलिस को संदेह है कि यह गिरोह इस तरह की गतिविधियों में पहले से शामिल रहा है। मामले की जांच जारी है।

पटना के प्राइवेट स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस वसूली पर डीएम ने लिया संज्ञान

पटना। मार्च-अप्रैल के महीने में बच्चों के स्कूलों में रिएडमिशन फी के अलावा अन्य अनावश्यक बोझ डालने से अभिभावकों का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। ऐसे में कुछ अभिभावकों ने इससे परेशान होकर प्राईवेट स्कूलों की शिकायत जिला प्रशासन से की,जिसपर एक्शन लेते हुए पटना जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किये है। पटना के प्राइवेट स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस वसूली को लेकर जिलाधिकारी ने साफ संदेश दिया है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दो महीने से अभिभावकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई प्राइवेट स्कूल निर्धारित फीस के अलावा अलग-अलग नामों पर अतिरिक्त रकम वसूल रहे हैं। एडमिशन फीस, ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी और एनुअल फी के अलावा भी कई तरह के छिपे शुल्क लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई स्कूल फी स्ट्रक्चर को लेकर स्पष्ट जानकारी भी शेयर नहीं कर रहे थे, जिससे अभिभावकों में भ्रम और नाराजगी दोनों बढ़ रही थी। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. ने ज्यादा तादाद में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया और सक्रियता के साथ फोरन कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ) को सख्त निगरानी रखने को कहा है। डीएम ने स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल बिना अनुमति फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकता और अतिरिक्त शुल्क वसूलना पूरी तरह अवैध है। प्रशासन ने सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी पूरी फी स्ट्रक्चर को सार्वजनिक करें। स्कूलों को नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर फी से जुड़ी सभी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि अभिभावकों को पहले से पूरी जानकारी मिल सके।

संविदा कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाने को लेकर विवाद

दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन के अंतर्गत 149-कसबा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी शुचिता को ताक पर रखने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा एक सोची-समझी रणनीति के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए संविदा कर्मचारियों (कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ) की अवैध रूप से महत्वपूर्ण चुनावी पदों पर नियुक्ति की गई है। कसबा की निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) पूर्णिमा दे द्वारा 10 अप्रैल 2026 को जारी ज्ञापन संख्या 93/इलेक्शन/149-कसबा/एजीई-26 के माध्यम से किया गया यह कृत्य एक गहरे षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। इस आदेश के तहत उन संवेदनशील भूमिकाओं में संविदा कर्मियों को तैनात किया गया है, जो विधिक रूप से केवल स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित हैं। भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार, मतदान जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों में संविदा कर्मियों का उपयोग वर्जित है क्योंकि उनमें स्थायी सेवा जैसी जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। चिह्नित किए गए ये सेक्टर सहायक मूल रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आईएसजीपीपी सेल के संविदा कर्मी बताए जा रहे हैं, जो वर्तमान में जिला परिषद में कार्यरत हैं। मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य पदनामों के साथ किया गया कथित फेरबदल है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 'सेक्टर सहायक' और 'सहायक सेक्टर अधिकारी' जैसे नए और गैर-मानक पदनामों का सृजन किया गया है, जिनका निर्वाचन आयोग की आधिकारिक शब्दावली में कोई स्थान नहीं है। बताया जाता है कि पूर्व में जारी आदेशों में इन्हीं व्यक्तियों को 'सेक्टर अधिकारी' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, किंतु आपत्ति होने की आशंका के चलते प्रशासनिक स्तर पर चतुराई दिखाते हुए केवल इनके पदनाम बदल दिए गए, जबकि उनकी भूमिका और कार्यक्षेत्र यथावत रखा गया है। इस गंभीर विसंगति को देखते हुए निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने उक्त विवादास्पद आदेश पर रोक लगाने और पेशेवर कदाचार एवं पक्षपातपूर्ण आचरण के लिए निर्वाचन अधिकारी को पदमुक्त करने का आग्रह किया है ताकि चुनाव की निष्पक्षता अक्षुण्ण बनी रहे।

चुनाव से पहले भारी मात्रा में नकदी जब्त

सिलीगुड़ी। विधानसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी महकमा के फांसीदेवा के मुरालिगंज चेकपोस्ट पर नाका जांच के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है।जानकारी के अनुसार, सिलीगुड़ी से बिहार जा रही एक चार पहिया वाहन को शुक्रवार रात रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 18 लाख 98 हजार 700 रुपये नकद बरामद हुए। यह कार्रवाई स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) टीम, पुलिस और केंद्रीय बलों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। तलाशी के दौरान गाड़ी में मौजूद लोग इस बड़ी रकम से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद पूरी रकम को जब्त कर लिया गया। टीम आगे की कार्रवाई जुट गई है।

दिल्ली में साइबर ठगी का भंडाफोड़ 14 आरोपितों को किया गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का पदार्फाश करते हुए 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह म्यूल बैंक खातों के जरिए लोगों से ठगी कर रहा था और गेमिंग ऐप के माध्यम से रकम को इधर-उधर कर उसका स्रोत छिपा रहा था। पुलिस ने आरोपितों के पास से 79 हजार रुपये नकद, 28 मोबाइल फोन, 17 पासबुक, तीन लैपटॉप और 23 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं।

दक्षिण-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने शनिवार को बताया कि, दक्षिण-पश्चिम जिले में दिल्ली में साइबर ठगी का भंडाफोड़, 14 आरोपित गिरफ्तार सक्रिय संदिग्ध बैंक खातों के विश्लेषण के दौरान इस संगठित गिरोह का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि आरोपित फर्जी निवेश योजनाओं, पार्ट-टाइम जॉब ऑफर और अन्य ऑनलाइन स्कैम के जरिए लोगों को निशाना बनाते थे। ठगी की रकम को म्यूल खातों में ट्रांसफर कर उसे कई स्तरों पर घुमाया जाता था, जिससे उसकी ट्रैकिंग बेहद कठिन हो जाती थी। उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को झांसे में लेते थे और उन्हें कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड हासिल कर लेते थे। इसके बाद इन्हीं खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी के पैसों को निकालने और ट्रांसफर करने में किया जाता था। मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी विश्लेषण, वित्तीय लेनदेन की जांच और फील्ड सर्विलांस के जरिए सबसे पहले मोहम्मद फैज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद फहाद का नाम बताया, जिसे शाहीन बाग इलाके से पकड़ा गया। आगे की जांच में सुवेब रब्बानी, सतेंद्र राठौर, शनी पाल और प्रीतम कुमार सहित कई अन्य आरोपितों की पहचान हुई। पुलिस ने नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में छापेमारी कर इन सभी को गिरफ्तार किया।

चारधाम यात्रा 2026: 14.5 लाख से अधिक पंजीकरण, केदारनाथ धाम सबसे आगे

एजेंसी (हि.स.)
देहरादून

फोटोः हि.स.

उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा-2026 को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अब तक कुल 14,54,897 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। इनमें केदारनाथ धाम के लिए सर्वाधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं।

पर्यटन विभाग के अनुसार शुक्रवार शाम पांच बजे तक केदारनाथ के लिए 4,95,173 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। इसके बाद बद्रीनाथ के लिए 4,29,416, गंगोत्री के लिए 2,62,485 और यमुनोत्री के लिए 2,55,609 पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के लिए अब तक 12,214 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। राज्य के विभिन्न ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों हरिद्वार, ऋषिकेश, नयागांव, हर्बर्टपुर और ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप पर आज कोई नया पंजीकरण दर्ज नहीं हुआ। हालांकि, ऑफलाइन पंजीकरण 17 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण 6 मार्च से लगातार जारी है। यात्रा कार्यक्रम के अनुसार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खोले जाएंगे। इसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारु, सुरक्षित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। यात्रा मार्गों, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा व्यवस्था और पंजीकरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट registration and touristcare. uk. gov. in, "Tourist Care Uttarakhand" मोबाइल एप तथा हेल्पलाइन नंबर 1364 और 0135-3520100 के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं आईआरसीटीसी की अधिकृत वेबसाइट के जरिए केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा टिकट की बुकिंग भी की जा रही।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री 12-14 अप्रैल तक पेरिस और बर्लिन का करेंगे दौरा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

विदेश सचिव विक्रम मिस्री 12-14 अप्रैल तक पेरिस (फ्रांस) और बर्लिन (जर्मनी) का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, पेरिस में विदेश सचिव, फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रिएन्स के साथ मिलकर भारत-फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे रक्षा, नागरिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, साइबर और डिजिटल, एआई, नवाचार, तथा लोगों के बीच आपसी मेलजोल और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने वाली पहलों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे हाल के वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी बात करेंगे।

दूसरी ओर बर्लिन में विदेश सचिव जर्मन विदेश सचिव डॉ. गेजा एंड्रियास वॉन गेयर के साथ मिलकर भारत-जर्मनी विदेश कार्यालय परामर्श की सह-अध्यक्षता करेंगे। इन चचाओं में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल होंगे, जिनमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, विकास सहयोग, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंध, तथा आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मामले शामिल हैं। विदेश सचिव की इसके अलावा दोनों जगह अन्य गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से भी मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि यह दौरा, जनवरी और फरवरी में क्रमशः जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज. और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्राओं के बाद हो रही है। यह भारत तथा यूरोप के बीच नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। यह दौरा दोनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा करने और प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।

उपलब्धि

इंसानों ने तय की अब तक की सबसे लंबी दूरी

नासा का मिशन आर्टेमिस-2 पूरा, दस दिनों बाद चांद के पास जाकर लौटे चारों अंतरिक्ष यात्री

एजेंसी (हि.स.)
वॉशिंगटन

फोटोः हि.स.

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस-2 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। मिशन में शामिल चारों अंतरिक्ष यात्री 10 दिनों की चंद्रमा यात्रा के बाद सुरक्षित धरती पर वापस लौट चुके हैं। मिशन में उन्होंने पृथ्वी से सबसे दूर रिकॉर्ड दूरी तय की।

नासा ने एक्स पर दी गई जानकारी में बताया कि चंद्र मिशन आर्टेमिस-2 के चारों अंतरिक्ष यात्री कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैनसेन सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका ओरियन अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर में उतरा। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास हुई यह लैंडिंग स्थानीय समय अनुसार रात 8:07 बजे (भारतीय समयानुसार 11 अप्रैल की सुबह 5:37 बजे) हुई। यह मिशन 1 अप्रैल को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सफलता पर बधाई दी है।

नासा ने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा, ₹रीड, विक्टर, क्रिस्टीना और जेरेमी, आपका घर में स्वागत है! आर्टेमिस क्क एस्ट्रोनॉट्स 11 अप्रैल को रात 8:07 बजे (अमेरिकी समय के अनुसार) उतर गए हैं, जिससे उनका ऐतिहासिक 10 दिनों का मिशन खत्म हो गया है।₹

1972 के बाद यह पहला मौका है, जब इस तरह चंद्र मिशन से वापसी हुई है। स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस मिशन में शामिल लोगों ने 690,000 मील से ज्यादा सफर किया। 10 दिन के इस मिशन की सफलता के बाद नासा आर्मेटिस-3 की तैयारी में जुट गया है। मौजूदा मिशन में अंतरिक्ष यात्री सिर्फ चंद्रमा के पास से गुजरे लेकिन अगले मिशन में यात्री चांद पर उतरेंगे।

सब-जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप फाइनल में मध्य प्रदेश की दोहरी दावेदारी

फाइनल की जंग आज, एमपी की पुरुष और महिला टीमों ने खिताबी मुकाबले में बनाई जगह

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

राजगीर, बिहार में चल रही सोलहवीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। बारह अप्रैल को होने वाले फाइनल मुकाबलों के लिए मंच तैयार है। पुरुष वर्ग के फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश का सामना उत्तर प्रदेश हॉकी से होगा, जबकि महिला वर्ग के खिताबी मुकाबले में हॉकी मध्य प्रदेश की टक्कर गत विजेता हॉकी झारखंड से होगी।

फोटोः हि.स.

पुरुष वर्ग में दोनों टीमें अब तक अपराजित रही हैं। सेमीफाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश ने दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव हॉकी को चार-दो से हराया, जबकि उत्तर प्रदेश हॉकी ने पिछले साल की विजेता हॉकी पंजाब को छह-दो से मात दी। यह मुकाबला पिछले वर्ष के तीसरे स्थान के मुकाबले की पुनरावृत्ति भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश विजयी रहा था। उत्तर प्रदेश हॉकी के शाहरुख अली इस प्रतियोगिता में चौदह गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं, जबकि नीतीश यादव ने सात गोल दागे हैं, जिनमें सभी गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए हैं। वहीं दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के धीरज पाल भी पांच गोल के साथ प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं। महिला वर्ग के फाइनल में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। गत विजेता हॉकी झारखंड ने सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश हॉकी को दो-शून्य से हराया, जबकि हॉकी मध्य प्रदेश ने हॉकी ओडिशा को दो-एक से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। महिला वर्ग में हॉकी मध्य प्रदेश की नुशीन नाज नौ गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं, जबकि हॉकी झारखंड की संदीपा कुमारी पांच गोल के साथ उनके पीछे हैं।

महिला वर्ग में तीसरे स्थान के लिए हॉकी ओडिशा का मुकाबला उत्तर प्रदेश हॉकी से होगा। वहीं पुरुष वर्ग में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव हॉकी का सामना हॉकी पंजाब से कांस्य पदक के लिए होगा। फाइनल मुकाबलों के साथ इस प्रतियोगिता का समापन रोमांचक अंदाज में होने की उम्मीद है, जहां देश की युवा प्रतिभाएं अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं।

बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो एकदिवसीय मैचों के लिए टीम घोषित की

एजेंसी (हि.स.)
ढाका

फोटोः हि.स.

बांग्लादेश की नई चयन समिति, जिसका नेतृत्व हबीबुल बशर कर रहे हैं, ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो एकदिवसीय मैचों के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय वही टीम बरकरार रखी है, जिसने पिछले महीने घरेलू मैदान पर पाकिस्तान को दो-एक से हराया था। श्रृंखला के पहले दो मुकाबले 17 और 20 अप्रैल को ढाका में खेले जाएंगे, जबकि तीसरा मुकाबला 23 अप्रैल को चट्टोग्राम में होगा।

टीम की कमान मेहदी हसन मिराज के हाथों में होगी। हालांकि हाल की जीत के बावजूद कुछ बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर सवाल बने हुए हैं। सैफ हसन और अफीफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन पारियों में क्रमशः 17.33 और 19 की औसत से रन बनाए थे, जो उम्मीदों से कम रहे।

तेज गेंदबाजी विभाग में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। चयनकर्ताओं ने नाहिद राना, तस्कीन अहमद, मुस्तफि जुर रहमान और शोरिफुल इस्लाम पर भरोसा बरकरार रखा है। हाल के समय में गेंदबाजों को बदल-बदल कर खिलाने की नीति के विपरीत यह एक स्थिर संयोजन माना जा रहा है।

बांग्लादेश की टीम के पाँच खिलाड़ी इस समय पाकिस्तान में चल रही लीग में खेल रहे हैं। ये सभी खिलाड़ी बारह अप्रैल को राष्ट्रीय टीम से जुड़ेंगे। रिपोर्टों के अनुसार, एकदिवसीय श्रृंखला समाप्त होने के बाद केवल मुस्तफि जुर रहमान ही वापस लीग में लौटेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच तीन बीस-बीस ओवरों के मुकाबले भी खेले जाएंगे।

बांग्लादेश की 15 सदस्यीय टीम इस प्रकार

मेहदी हसन मिराज (कप्तान), सौम्य सरकार, सैफ हसन, तंजीद हसन, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदोय, लिटन दास (विकेटकीपर), अफीफ हुसैन, महिदुल इस्लाम, रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, मुस्तफि जुर रहमान, तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम और नाहिद राना।

ला लीगाः रियल मैड्रिड ने गिरोना के साथ ड्रॉ खेलकर अंक गंवाए

एजेंसी (हि.स.)
मैड्रिड

फोटोः हि.स.

स्पेन की शीर्ष फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा में खिताब की दौड़ और रोमांचक हो गई है। रियल मैड्रिड को गिरोना के खिलाफ 1-1 की बराबरी पर संतोष करना पड़ा, जिससे शीर्ष पर काबिज बार्सिलोना को अपनी बढ़त और मजबूत करने का मौका मिल गया है। मुकाबले में पहला गोल दूसरे हाफ के छह मिनट बाद फेडेरिको वाल्वेर्दे ने किया, जिससे रियल को बढ़त मिली। हालांकि यह बढ़त ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और 62वें मिनट में थोमस लेमार ने शानदार गोल दागकर गिरोना को बराबरी दिला दी।

इस परिणाम के बाद बार्सिलोना 76 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद रियल मैड्रिड उससे छह अंक पीछे है और एक मुकाबला अधिक खेल चुका है। अब बार्सिलोना के पास अपनी बढ़त नौ अंकों तक पहुंचाने का शानदार अवसर है। रियल मैड्रिड ने इस मुकाबले में मजबूत टीम उतारी थी, क्योंकि उसे अगले सप्ताह एक अहम मुकाबला खेलना है, जिसमें पिछली हार की भरपाई करना जरूरी होगा। किलियन एमबाप्पे, विनीसियस जूनियर और जूड बेलिंघम जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरे, लेकिन टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पहले हाफ में रियल के पास गेंद पर नियंत्रण ज्यादा रहा, लेकिन वह साफ मौके बनाने में नाकाम रहा। गिरोना ने रक्षात्मक रणनीति अपनाई और जवाबी हमलों पर ध्यान दिया। गिरोना के खिलाड़ी अजेद्दीन उनाही का एक जोरदार शॉट भी देखने को मिला, जिसे गोलकीपर आंद्री लुनिन ने शानदार तरीके से रोक लिया।

बीएचयू दक्षिणी परिसर में सॉफ्टबॉल के गुर सीख रहे प्रशिक्षक

तीन दिवसीय कार्यशाला में ऑफिशिएटिंग एवं कोचिंग तकनीक की प्रशिक्षकों एवं रेफरी को दी जा रही जानकारी

एजेंसी (हि.स.)
वाराणसी

फोटोः हि.स.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के राजीव गांधी दक्षिण परिसर (आर.जी.एस.सी.), बरकछा में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में दूसरे दिन शनिवार को 'सॉफ्टबॉल' खेल के ऑफिशिएटिंग एवं कोचिंग तकनीक की प्रशिक्षकों एवं रेफरी को जानकारी दी गई। ह्लसॉफ्टबॉल में उन्नत नियम व्याख्या, ऑफिशिएटिंग एवं कोचिंग तकनीकह्व विषयक कार्यशाला में भारत में सॉफ्टबॉल के बढ़ते महत्व तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं मानकीकृत ऑफिशिएटिंग के महत्व को बताया गया। दक्षिणी परिसर के आचार्य प्रभारी प्रो. बी.एम.एन.कुमार के अनुसार कार्यशाला का उद्देश्य खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं रेफरी की तकनीकी एवं व्यावहारिक दक्षताओं का विकास करना है।

उन्होंने बताया कि कार्यशाला का आयोजन स्पोर्ट्स बोर्ड, आर.जी.एस.सी., बी.एच.यू ने किया है। कार्यशाला के पहले दिन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रो. ए. के. नेमा (महासचिव, स्पोर्ट्सबोर्ड, बी.एच.यू.) ने खेलों में अनुशासन, नियमों की समझ एवं प्रशिक्षित अधिकारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथियों के रूप में आईसीएमआर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पंकज सिंह तथा सेंट जोसेफ कॉलेज, बेंगलुरु के खेल निदेशक जितेंद्र मेवारा ने खेलों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पेशेवर दृष्टिकोण पर खासा जोर दिया। आचार्य प्रभारी ने बताया कि कार्यशाला में दो दिन ऑफिशिएटिंग मैकेनिक्स, कोचिंग तकनीक, शारीरिक फिटनेस, प्रतियोगिता प्रबंधन, स्कोरिंग प्रणाली एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विस्तृत सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार की कार्यशालाएं खेल संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उल्लेखनीय है कि सॉफ्टबॉल, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लोकप्रिय खेल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि सॉफ्टबॉल का विकास इंडोर बेसबॉल नामक खेल से हुआ है, जो पहली बार खेला गया था। शिकागो में 1887 में इसका जन्म हुआ। सॉफ्टबॉल का मूल बेसबॉल के समान ही है। बल्लेबाजी और फील्डिंग की रणनीति भी समान है लेकिन सॉफ्टबॉल बहुत छोटे मैदान पर खेला जाता है और एक मैच केवल सात पारियों का होता है।

प्रीमियर लीगः वेस्ट हैम की जीत से टॉटेनहम रेलीगेशन क्षेत्र में, दे जेर्बी को बचाव की उम्मीद

एजेंसी (हि.स.)
लंदन

फोटोः हि.स.

इंग्लैंड की शीर्ष फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने वूल्वरहैम्प्टन वांडरर्स को 4-0 से हरा दिया। इस नतीजे के बाद टॉटेनहम हॉटस्पर पहली बार इस सत्र में रेलीगेशन क्षेत्र में पहुंच गया है। टॉटेनहम अब वेस्ट हैम से दो अंक पीछे है और उसका अगला मुकाबला रविवार को सुंदरलैंड से होगा।

वेस्ट हैम की ओर से वैलेंटीन कास्टेलानोस ने दूसरे हाफ के मध्य में तीन मिनट के भीतर दो गोल दागे, जबकि हाफ टाइम से ठीक पहले कॉन्स्टैन्टिनोस माव्रोपानोस ने हेडर से टीम को बढ़त दिलाई थी। मैच के अंतिम चरण में कॉर्नर से आए मौके पर एक शानदार वॉली के जरिए चौथा गोल दागा गया। इस हार के साथ वूल्व्स अंक तालिका में सबसे नीचे बने हुए हैं और उनके निचली लीग में जाने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। टॉटेनहम के नए प्रबंधक रॉबर्टो दे जेर्बी ने कहा कि उनकी टीम को रेलीगेशन से बचने के लिए साहस और आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा। उन्होंने खिलाड़ियों से साफ रणनीति के साथ मैदान पर उतरने और बिना ज्यादा दबाव लिए अपना स्वाभाविक खेल दिखाने की अपील की। दे जेर्बी ने कहा कि टीम को लड़ने का जज्बा, साहस और आक्रामकता दिखानी होगी। दे जेर्बी को पाँच साल का अनुबंध दिया गया है और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती टीम को रेलीगेशन से बचाना है। उन्होंने कहा कि क्लब की पहचान हमेशा आक्रामक फुटबॉल और गोल करने की मानसिकता से जुड़ी रही है और वे उसी भावना को वापस लाना चाहते हैं।

दर्पण विशेष

अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवसः जब यूरी गागरिन ने पहली बार लांघी थी ब्रह्मांड की दहलीज

हर साल 12 अप्रैल को पूरी दुनिया 'अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस' के रूप में मनाती है। यह दिन न केवल अंतरिक्ष विज्ञान की महानतम उपलब्धियों को याद करने का है, बल्कि यह उस अदम्य साहस का भी प्रतीक है, जिसने इंसान को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमाओं से बाहर निकलकर सितारों की दुनिया में कदम रखने का हौसला दिया।

1961 का वह ऐतिहासिक पलः 108 मिनट और बदल गया इतिहास

आज ही के दिन, 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ (अब रूस) के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने 'वोस्तोक-1' अंतरिक्ष यान में सवार होकर इतिहास रचा था। वह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने थे। महज 108 मिनट की उस पहली अंतरिक्ष यात्रा ने सदियों पुराने इस मिथक को तोड़ दिया था कि इंसान पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जीवित नहीं रह सकता। गागरिन की इस सफलता के बाद ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 12 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर इस दिवस के लिए घोषित किया। रूस में इस दिन को 'कॉस्मोनॉटिक्स डे' के रूप में मनाया जाता है।

भारत का गौरवः 'गगनयान' के जरिए अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने की तैयारी

जब हम मानव अंतरिक्ष यात्रा की बात करते हैं, तो भारत का नाम भी गर्व के साथ लिया जाता है। 3 अप्रैल 1984 को विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, इस सवाल पर उनका जवाब– 'सारे जहाँ से अच्छा'–आज भी हर भारतीय के जहन में गूँजता है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने महत्वाकांक्षी 'गगनयान' मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। इस मिशन का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों (गगननॉट्स) को स्वदेशी तकनीक से तैयार यान के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। इस सफलता के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जिनके पास मानव को अंतरिक्ष में भेजने की अपनी क्षमता है।

आर्टेमिस से मंगल तक का सफर

आज यह दिवस एक ऐसे समय में आया है जब नासा का आर्टेमिस-2 मिशन हाल ही में चंद्रमा की परिक्रमा कर सुरक्षित वापस लौटा है। अब वैज्ञानिक केवल चंद्रमा तक सीमित नहीं रहना चाहते। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा मिलकर अब मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की योजना पर काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष पर्यटन के बढ़ते चलन ने अब आम नागरिकों के लिए भी अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक के समन्वय से इंसान अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है।

मुख्य तथ्य

प्रथम महिलाः वेलेंटीना तेरेश्कोवा (1963 में अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला)। **प्रथम चंद्र भ्रमणः** नील आर्मस्ट्रांग (1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव)। **अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन :** पिछले 24 वर्षों से लगातार कोई न कोई मानव अंतरिक्ष में मौजूद है।

अंतरिक्ष यात्राः शरीर और विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती

इंसान के लिए अंतरिक्ष में रहना उतना आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार, अंतरिक्ष यात्रियों को कई शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। **'स्पेस एनीमिया' (खून की कमी)**: हालिया शोधों से पता चला है कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती हैं। **हड्डियों का घनत्वः** बिना गुरुत्वाकर्षण के रहने से अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियाँ हर महीने लगभग 1% से 1.5% तक कमजोर हो जाती हैं। यही कारण है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनपर रोज 2 घंटे विशेष व्यायाम करना पड़ता है। **लंबाई का बढ़नाः** गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण रीढ़ की हड्डी फैलती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री की लंबाई 2 इंच तक बढ़ सकती है।

अंतरिक्ष का कचरा

एक बढ़ता खतरा जैसे-जैसे मानव अंतरिक्ष मिशन बढ़ रहे हैं, पृथ्वी की कक्षा में कचरा भी बढ़ रहा है। वर्तमान में पृथ्वी के चारों ओर 30,000 से अधिक मलबे के टुकड़े तैर रहे हैं, जो पुरानी सैटेलाइट्स या रॉकेट के हिस्से हैं। ये छोटे-छोटे टुकड़े 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से घूम रहे हैं। यदि एक छोटा सा बोल्ट भी किसी अंतरिक्ष यान से टकरा जाए, तो वह बम जैसा धमाका कर सकता है। अब वैज्ञानिक इस मलबे को साफ करने के लिए 'मैग्नेटिक नेट' और 'लेजर' तकनीक पर काम कर रहे हैं।

इतिहास

इस दिवस की जड़ें शीत युद्ध के उस दौर से जुड़ी हैं, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष की श्रेष्ठता को लेकर होड़ मची थी। यूरी गागरिन का पराक्रमः 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के पायलट यूरी गागरिन ने 'वोस्तोक-1' यान से अंतरिक्ष की पहली यात्रा की। संयुक्त राष्ट्र की घोषणाः इस ऐतिहासिक घटना की 50वीं वर्षगांठ पर, यानी 7 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष प्रस्ताव (65/271) पारित किया। इसके तहत 12 अप्रैल को 'अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस' के रूप में घोषित किया गया।

उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र और वैज्ञानिक समुदाय इस दिन को मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण लक्ष्य रखते हैं। शांतिपूर्ण अन्वेषणः इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों और पूरी मानवता के कल्याण के लिए हो, न कि युद्ध या हथियारों की होड़ के लिए। विज्ञान के प्रति जागरूकताः युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। अंतरराष्ट्रीय सहयोगः अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई अकेला देश सफल नहीं हो सकता। यह दिवस देशों को आपसी मतभेद भुलाकर साथ मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का संदेश देता है।

महत्व

आज के दौर में अंतरिक्ष विज्ञान केवल शोध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। वैश्विक संचारः आज हम जो इंटरनेट, जीपीएस और मोबाइल कॉल का उपयोग करते हैं, वह अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों की ही देन है। जलवायु परिवर्तन की निगरानीः अंतरिक्ष से ही वैज्ञानिक पृथ्वी के बढ़ते तापमान, पिघलते ग्लेशियर और समुद्री स्तर की सटीक निगरानी कर पा रहे हैं। भविष्य की सुरक्षाः क्षुद्रग्रहों से पृथ्वी की रक्षा करने और भविष्य में दूसरे ग्रहों (जैसे मंगल) पर मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं को तराशने के लिए यह दिवस एक संकल्प की तरह है। भारत के लिए भी यह दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 'गगनयान' मिशन के माध्यम से अपने स्वयं के अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के बेहद करीब हैं। यह मिशन न केवल हमारी तकनीकी शक्ति को दिखाएगा, बल्कि भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पंचकूला जिले से जनजागरूकता अभियान की शुरूआत की

कहा- नारी शक्ति वंदन अधिनियम से नीति निमार्ता बनेगी महिलाएं

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। इसको लागू करने के लिए आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अधिनियम के प्रति जनजागरूकता लाने के लिए 11 अप्रैल से अभियान शुरू किया गया है , यह अभियान 20 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चलेगा जिसमें महिलाओं व आम जनमानस को अधिनियम की जानकारी देने और उनसे जुड़ाव बढ़ाने की तैयारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री आज पंचकुला में इस अभियान की शुरूआत करने के बाद मीडिया से बात कर रही थी।

आरती सिंह राव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जानकारी एवं इसके लाभ गिनवाते हुए बताया कि इस अधिनियम से महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन है, जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह अधिनियम केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे महिलाओं को नीति निर्माण में अधिक भागीदारी का अवसर मिलेगा और लोकतंत्र और मजबूत होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में महिलाओं की मतदान में भागीदारी लगातार बढ़ रही है और कई स्थानों पर यह पुरुषों से भी अधिक है। इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है, जिसे यह अधिनियम संतुलित करेगा।

उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिलता है, तो शासन अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बनता है। पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका उदाहरण है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी जैसे मुद्दों पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। आरती सिंह राव ने कहा कि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं ने महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और जन-धन योजना जैसी पहलों ने महिलाओं को सशक्त बनाया है।

उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ-साथ महिलाओं को अब राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ाना आवश्यक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी दिशा में एक ठोस कदम है।

स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस जनजागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और महिलाओं के सशक्तिकरण के इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने में योगदान दें।

हरियाणा के राज्यपाल ने जनगणना 2027 के लिए लोगों से स्व-गणना करने के लिए की अपील

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

निदेशक, जनगणना एवं नागरिक पंजीकरण (हरियाणा), गृह मंत्रालय द्वारा आज माननीय राज्यपाल हरियाणा, प्रो. अशीम कुमार घोष से शिष्टाचार भेंट की गई तथा उन्हें जनगणना 2027 से संबंधित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर जनगणना गतिविधियों से संबंधित एक कैलेंडर भी जारी किया गया। हरियाणा राज्य में स्व-गणना (री'ा-एल्लथ्रे१ं३ङ्गल्ल) की सुविधा 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध रहेगी। सभी नागरिक मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे री'ा-एल्लथ्रे१ं-३ङ्गल्ल पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। यह एक सरल, सुरक्षित एवं आधुनिक पहल है। इसके पश्चात, 1 मई से 30 मई 2026 तक पूरे राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (ल्ल्न४री'२३ल्ल्रॅ डस्री१ं३ङ्गल्ल२) के अंतर्गत प्रगणक प्रत्येक घर का दौरा करेंगे।

इस मौके पर माननीय राज्यपाल हरियाणा ने श्री ललित जैन, निर्देशक, जनगणना विभाग, हरियाणा तथा उनकी टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके आंकड़ों के आधार पर हरियाणा के विकास की दिशा और नीति निर्धारित की जाएगी।

राज्यपाल ने नागरिकों से आान किया कि वे स्व-गणना का अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि यह अत्यंत सुविधाजनक एवं सुगम है। इससे समय और संसाधनों की बचत भी होगी। अंत में, प्रो. घोष ने सभी हरियाणा निवासियों से अपील की कि वे जनगणना कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि यह महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

भारत द्वारा वित्तपोषित भूटान की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना पर 7 वर्षों के बाद काम फिर से शुरू हुआ

सिटी दर्पण संवाददाता
थिंपू

पुनात्सांगचू-कजलविद्युत परियोजना (पीएचईपी-क) पश्चिमी भूटान के वांगडुफोड्रंग जोंगखाग में पुनात्सांगचू नदी पर रन-ऑफ-द-रिवर योजना है। पीएचईपी-क की स्थापित क्षमता 1200 मेगावाट है और यह प्रति वर्ष औसतन 5670 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी। पीएचईपी-क भूटान में चल रही सबसे बड़ी परियोजना है। एक बार पूरा हो जाने पर इससे भूटान की जलविद्युत क्षमता में लगभग 30% की वृद्धि होगी और यह लगभग 4700 मेगावाट हो जाएगी और प्रति वर्ष औसतन 5,670 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। भारत सरकार इस परियोजना को वित्तपोषित कर रही है। वित्तपोषित राशि में 40% अनुदान और 60% ऋण शामिल है। पीएचईपी-कद्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली भारत को दोनों देशों द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेची जाएगी जिस पर परियोजना आरंभ होने के समय सहमति होगी। निर्माण कार्य 11 नवंबर 2008 को शुरू हुआ था और आरंभिक तौर पर परियोजना से उत्पादन आरंभ होने का समय नवंबर 2015 निर्धारित किया गया था। हालांकि, परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान, सतह और भूमिगत कार्यों में महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसके कारण डिजाइन में कई बदलाव करने पड़े। 2013 से बांध के दाहिने किनारे की ढलान के अस्थिर होने के कारण बांध के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप बांध के जारी कार्यों को 2019 से निलंबित कर दिया गया। दोनों सरकारों और संबंधित एजेंसियों ने कई बैठकों में और अध्ययनों के द्वारा इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

लुवास यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने किया नेचर कैंप थापली का भ्रमण

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

थापली नेचर कैंप में लुवास यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का दूसरा दिन उत्साह और सीख से भरपूर रहा। सुबह की ताजगी भरी शुरूआत के साथ विद्यार्थियों ने ट्रेकिंग गतिविधि में भाग लिया, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ-साथ पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को करीब से समझा।

ट्रेकिंग के दौरान छात्रों ने पहाड़ी क्षेत्रों की जैव विविधता, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह अनुभव न केवल रोमांचक रहा बल्कि विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। प्राकृतिक परिवेश में चलते हुए छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी महसूस किया। इस अवसर पर युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को प्रकृति के महत्व, पर्यावरण संतुलन और मानव जीवन में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को जागरूक करते हुए कहा कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए और इसके संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए इसके अलावा, क्षेत्र के रेंज अधिकारी ने भी विद्यार्थियों को वन क्षेत्र की विशेषताओं, वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के नियमों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने बताया कि वन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और इनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। उनके द्वारा दी गई जानकारी छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक रही। दिन भर चली इन गतिविधियों ने विद्यार्थियों में टीमवर्क, अनुशासन और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया। थापली नेचर कैंप का यह दूसरा दिन विद्यार्थियों के लिए यादगार अनुभव साबित हुआ, जिसने उन्हें प्रकृति के करीब लाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया। इस प्रकार, यह कैंप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उन्हें प्रकृति के साथ जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है।

IIT रोपड़ का ई-समिट'26 शुरू, असंभव को संभव बनाने का आह्वान

सिटी दर्पण संवाददाता
रोपड़

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने आज अपने वार्षिक उद्यमिता और नवाचार शिखर सम्मेलन ई-समिट'26 का उद्घाटन किया। यह दो दिवसीय आयोजन E-Cell IIT रोपड़ द्वारा टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। 11 और 12 अप्रैल 2026 को रोपड़ परिसर में विद्यार्थी, स्टार्टअप, निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख लोग एक साथ जुट रहे हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजेश कुमार पाठक, सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड , भारत सरकार तथा सम्मानित अतिथि के रूप में डॉ. राजीव गौतम, अध्यक्ष, HORIBA इंडिया उपस्थित रहे। IIT रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव अहूजा ने समारोह की अध्यक्षता की। उद्घाटन सत्र में प्रो. राजीव अहूजा ने कहा कि IIT रोपड़ अब डीप-टेक उद्यमिता का एक मजबूत केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि संस्थान से अब तक 450 से अधिक स्टार्टअप इनक्यूबेट हो चुके हैं, जो यहां बने पारिस्थितिकी तंत्र में युवा नवाचारकों के बढ़ते विश्वास को दशार्ता है। उन्होंने विद्यार्थियों और शोधकताओं को परंपरागत रास्तों से हटकर नवाचार और अनुसंधान के जरिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। हमारे युवा उद्यमी असल समस्याओं को असल तकनीक से सुलझा रहे हैं। इस समिट की ऊर्जा ठीक उसी अग्रणी भावना को दशार्ती है जिसके लिए IIT रोपड़ जाना जाता है, प्रो. अहूजा ने कहा।

अपने संबोधन में श्री राजेश कुमार पाठक ने भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान एवं विकास और नवाचार कोष के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सरल शब्दों में समझाया कि शुरूआती चरण के स्टार्टअप इस कोष के जरिए अनुदान और वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक संस्था है, देशी तकनीक के विकास और व्यावसायीकरण में लगी भारतीय कंपनियों को वित्तीय सहायता देती है। श्री पाठक ने ई-समिट'26 के आयोजन में जुटे विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा, ऐसे आयोजन केवल विचारों का उत्सव नहीं होते। ये भारत की अगली पीढ़ी के तकनीकी उद्यमों की नींव होते हैं। HORIBA इंडिया के अध्यक्ष डॉ. राजीव गौतम ने जापान की अग्रणी परिशुद्धता उपकरण और माप प्रौद्योगिकी कंपनी में अपने लंबे अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों को व्यावहारिक सलाह दी। उन्होंने कहा कि केवल तकनीकी दक्षता ही एक सफल करियर की गारंटी नहीं होती। अच्छा आचरण, सकारात्मक दृष्टिकोण और विविध टीमों के साथ काम करने की क्षमता भी उतनी ही, और कई बार उससे भी अधिक, जरूरी होती है। उनके संबोधन को उपस्थित विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने खूब सराहा। उद्घाटन के अलावा समिट में सीखने और अनुभव से भरे कई कार्यक्रम हैं। पहले दिन स्टार्टअप एक्सपो, बुक फेयर और इंटर्नशिप फेयर एक साथ चले, जिससे विद्यार्थियों को उभरती कंपनियों और करियर के अवसरों तक सीधी पहुंच मिली।

सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता में कालका कॉलेज की छात्राओं का शानदार प्रदर्शन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राजकीय महाविद्यालय कालका की प्राचार्या डॉक्टर गीता सुखीजा के कुशल नेतृत्व में महाविद्यालय की ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन क्लब की तीन छात्राओं ने जिला स्तरीय अंतर कॉलेज सड़क सुरक्षा प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यह प्रतियोगिताएं एसएमएमडी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पंचकूला में आयोजित की गई थी।

ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन क्लब की प्रभारी डॉक्टर मनीषा के मार्गदर्शन में छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बीसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा कशिश ने पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रिया ने स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राचार्या डॉक्टर गीता सुखीजा ने छात्राओं के प्रयासों की सराहना की और उन्हें समाज में सड़क सुरक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

पंजाब मॉडर्न कंपलेक्स में ड्रेनेज डालने का काम शुरू

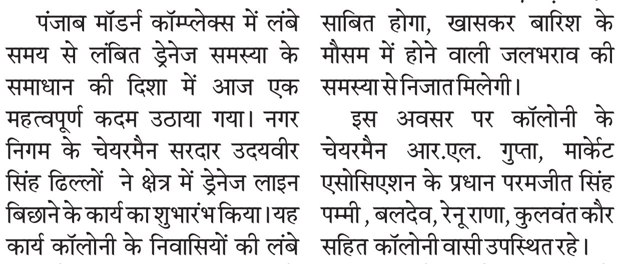

सिटी दर्पण संवाददाता
जीरकपुर

पंजाब मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में लंबे समय से लंबित ड्रेनेज समस्या के समाधान की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नगर निगम के चेयरमैन सरदार उदयवीर सिंह ढिल्लों ने क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। यह कार्य कॉलोनी के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे आज आखिरकार पूरा किया गया।

कॉलोनी के प्रधान अरविंद राणा ने इस मुद्दे को कई बार नगर निगम प्रशासन के समक्ष उठाया था। उनके लगातार प्रयासों के चलते यह कार्य संभव हो सका। ड्रेनेज लाइन बिछाने का यह कार्य कॉलोनी वासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, खासकर बारिश के मौसम में होने वाली जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी।

इस अवसर पर कॉलोनी के चेयरमैन आर.एल. गुप्ता, मार्केट एसोसिएशन के प्रधान परमजीत सिंह पम्मी , बलदेव, रेनू राणा, कुलवंत कौर सहित कॉलोनी वासी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में अरविंद राणा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार दीपइंदर सिंह ढिल्लों और अन्य नेताओं का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी क्षेत्र के विकास कार्य इसी तरह जारी रहेंगे।

हरियाणा में 13 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाएगी बैसाखी

आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बैसाखी पर्व की तैयारियों का लिया जायजा

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा सरकार द्वारा 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों के उपायुक्तों के साथ बैसाखी पर्व की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि पंचकूला, अंबाला, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, फरीदाबाद, जींद, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में बैसाखी पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके अलावा अन्य जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।

डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि बैसाखी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व रबी की फसल के पकने का प्रतीक है। जब गेहूं की फसल खेतों में सुनहरी होकर लहलहाती है, तो किसान अपनी मेहनत का फल देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी खुशी के अवसर पर बैसाखी मनाई जाती है। इस दिन लोग रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं, पारंपरिक नृत्य करते हैं और ढोल-नगाड़ों की धुन पर झूमते हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लेजर शो का आयोजन किया जाए और कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाए।

इसके अलावा भांगड़ा, गिद्दा तथा बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में उपस्थित उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आश्वासन दिया कि जिला स्तर पर इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए बैसाखी पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा। बैठक के उपरांत उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि 13 अप्रैल, सोमवार को बैसाखी पर्व का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम में पंजाबी भांगड़ा, गिद्दा, गतका सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी।

इस मौके पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खंगवाल, आईएएस तथा अतिरिक्त निदेशक श्री मनीष कुमार लोहान भी उपस्थित थे।

संक्षिप्त-समाचार

बीबा ने पेश किया समकालीन समर फेस्टिव एडिट

चंडीगढ़। भारत का प्रमुख होमग्रोन फैशन ब्रांड बीबा बैसाखी के अवसर पर अपना समकालीन समर फेस्टिव एडिट लेकर आया है। यह कलेक्शन ऐसे समय में पेश किया गया है जब पंजाब पूरे उत्साह के साथ जश्न में डूबा होता है। ढोल की थाप, सरसों के खिले खेत और फसल के मौसम की वह सामूहिक खुशी, जो इस त्योहार को देश के सबसे जीवंत उत्सवों में शामिल करती है। यह एडिट अवसर, परंपरा और आधुनिकता के संतुलन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि आज की भारतीय महिला अपने खास पलों में सहज और खूबसूरत महसूस कर सके। इस कलेक्शन में बैसाखी की ऊर्जा साफ झलकती है। सरसों और केसरिया जैसे रंग इसमें प्रमुखता से उभरते हैं, जो इस मौसम और पंजाब की पहचान से जुड़े हुए हैं। इनके साथ हल्के फ्लोरल प्रिंट्स और संतुलित रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो पारंपरिक उत्सव को एक आधुनिक अंदाज में पेश करते हैं। हल्के कॉटन और मुल के कपड़े इसे पूरे दिन पहनने के लिए आरामदायक बनाते हैं। कुर्ता सेट, प्रिंटेड सूट सेट, शरारा सेट और ए-लाइन सिलुएट्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि सुबह की अरदास से लेकर शाम के जश्न तक आसानी से पहने जा सकें। इसके साथ ही कुर्तियां, टॉप और बॉटम्स जैसे सेपरेट्स इस कलेक्शन को और भी उपयोगी बनाते हैं।

समर्या क्रिएशन ने लॉन्च किया औमोरा म्यूज़िक

चंडीगढ़। भारत की क्रिएटर इकॉनमी ने आज संगीत जगत में सबसे विश्वसनीय कदम रखा। देश की पहली इंटीग्रेटेड क्रिएटर-फर्स्ट कंपनी समर्या क्रिएशन ने आज मुंबई के द क्लब, अंधेरी वेस्ट में औमोरा म्यूज़िक के आधिकारिक लॉन्च की घोषणा की - और इसके संस्थापक पार्टनर हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी गीतकार सामेर अंजान। यह महज एक म्यूज़िक लेबल नहीं है। यह उस सोच का जवाब है जो आज तक भारतीय संगीत में गायब थी - जहाँ एल्गोरिदम नहीं, कलाकार तय करेगा कि संगीत कैसा हो। चार दशकों में 640 से ज्यादा हिंदी फिल्मों के लिए 4,000 से अधिक गाने लिखने वाले सामेर अंजान यहाँ ब्रांड एंबेसेडर नहीं, बल्कि निमार्ता हैं। औमोरा म्यूज़िक पहले से ही 150+ प्लेटफॉर्म्स पर 19 ट्रैक्स के साथ लाइव है, 150+ ओरिजिनल कम्पोज़िशन रिलीज के लिए तैयार हैं - बॉलीवुड, भक्ति, लोक, बाल संगीत, रैप और कंटेम्पोरेरी पॉप सभी जॉनर में। मैंने 4,500 गाने लिखे हैं। मैं जानता हूँ क्या टिकता है और क्या अगली सुबह भूल जाता है। औमोरा म्यूज़िक उन कलाकारों का घर है जिनके पास कहने के लिए कुछ असली है।ह्ल- सामेर अंजान, संस्थापक, औमोरा म्यूज़िक लेबल के क्रिएटिव इंजन हैं कम्पोजर नील गांधी और निरज विश्वकर्मा - दो ऐसे नाम जो परंपरा को तोड़कर यहाँ पहुँचे हैं।

टीडीआई कॉनॉट एस्टेट में भागवत कथा के साथ सेवा दर्शन की पहल

राजपुरा ।टीडीआई कॉनॉट एस्टेट, राजपुरा में चल रही श्रीमद भागवत कथा अब एक बड़े सामाजिक संदेश का माध्यम बन चुकी है। 6 अप्रैल से शुरू हुए इस आयोजन में जहां हजारों श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं, वहीं कथा के माध्यम से सेवा दर्शन और गौ सेवा का संदेश व्यापक स्तर पर फैल रहा है। प्रसिद्ध कथावाचक देवी चित्रलेखा जी ने अपने प्रवचनों में स्पष्ट किया कि आज के समय में धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उसे सेवा से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उल्लेख करते हुए इसे देश में चल रहे सबसे बड़े सेवा अभियानों में से एक बताया, जहां बीमार और घायल गौवंश का आधुनिक तरीके से उपचार किया जा रहा है। देवी चित्रलेखा जी ने कहा कि आज समाज को कथा सुनने के साथ-साथ सेवा को अपनाने की जरूरत है। जब हम किसी असहाय जीव की रक्षा करते हैं, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल इस सोच को जमीन पर उतारने का एक बड़ा उदाहरण है। कथा के दौरान सेवा दर्शन को एक जनआंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के कार्यों की जानकारी भी साझा की जा रही है, जिससे लोग सीधे इस पहल से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रोनिका इंडिया 2026 ग्रेटर नोएडा में शुरू

चंडीगढ़। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रोनिका इंडिया 2026 के उद्घाटन दिवस पर नीति संकेतों और व्यावसायिक इरादों का स्पष्ट मिश्रण देखने को मिला, जब वरिष्ठ सरकारी नेता और उद्योग हितधारक इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में एकत्र हुए। भूपिंदर सिंह, प्रेसिडेंट - आईएमईए, मेस्से मुएनचेन और सीईओ, मेस्से मुएनचेन इंडिया ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिका इंडिया और प्रोडक्ट्रोनिका इंडिया अब एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हो चुके हैं, जहाँ व्यावसायिक इरादा स्पष्ट और परिणाम-उन्मुख है। कंपनियाँ स्पष्ट प्राथमिकताओं के साथ आ रही हैं चाहे वह सोर्सिंग हो, साझेदारियाँ हों या निवेश और शुरूआती गति वास्तविक, मापनीय परिणामों की ओर बदलाव को दर्शाती है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि, श्री सुरेश कुमार खन्ना, माननीय वित्त मंत्री और संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और यह एक स्थिर तथा निवेश-तैयार राज्य के रूप में उभरा है। मजबूत औद्योगिक विकास, बढ़ते निर्यात और विनिर्माण पर फोकस के साथ, हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहाँ व्यवसाय आत्मविश्वास के साथ विस्तार कर सकें।

गुरबचन सिंह 'आजाद' की पुस्तकों का विमोचन

डेराबस्सी> पंजाबी साहित्य सभा (पंजीकृत) की ओर से एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पुआध क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कवि गुरबचन सिंह 'आजाद' के 82वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी दो पुस्तकों 'मेरा जीवन, मेरी गाथा' (तीसरा संस्करण) और कविता संग्रह 'रंग-बारंग' (दूसरा संस्करण) का विमोचन किया गया। पूर्व विधायक एनके. शर्मा ने 'आजाद' के साहित्यिक योगदान की - सराहना करते हुए कहा कि उनकी रचनाएं क्षेत्र की अमूल्य धरोहर हैं। इस मौके पर उनके पुत्र रोटेरियन भूपेंद्र सैनी पूर्व नगर कौंसिल प्रधान डेराबस्सी,समाजसेवी हरिंदर हनी मौजूद थे।